PAPERS LAID ON THE TABLE THIRTEENTH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE (1954-55)

DIWAN CHAM AN LALL (Punjab): Sir, I have the honour to lay on the Table a copy of the Thirteenth Report of the Public Accounts Committee (1954-55) on the Appropriation Accounts (Posts and Telegraphs) and (Railways), 1951-52 and 1952-53, Vol. I Report. *[Placed in Library. See No.* S-287/55.]

MINISTRY OF LABOUR NOTIFICATIONS PUBLISHING (I) AMENDMENTS TO THE MYSORE GOLD MINES REGULATIONS, 1953, AND (ii) THE MINES RULES, 1955.

REVISED BUDGET ESTIMATES FOR 1954-55 AND BUDGET ESTIMATES FOR 1955-56 OF EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION.

THE DEPUTY MINISTER FOR LABOUR (SHRI A BID ALI) : Sir, I lay on the Table a copy of each of the following Notifications under sub-section (7) of section 59 of the Mines Act, 1952:—

(i) Ministry of Labour Notification S.R.O. No. 525, dated the 28th February, 1955, publishing certain amendments to the Mysore Gold Mines Regulations, 1953. [Placed *in Library. See No.* S-284/55.]

(ii) Ministry of Labour Notification S.R.O. No. 1421. dated the 2nd July, 1955, publishing the Mines Rules, 1955. I *Placed in Library. See No.* S-285/55.]

Sir. I also lay on the Table, under section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948, a copy of the Revised Budget Estimates for the year 1954-55 and the Budget Estimates for the year 1955-56 of the Employees' State Insurance Corporation. *[Placed in Library. See No.* S-289-55.]

THE ABDUCTED PERSONS (RECOVERY AND RESTORATION) CONTINUANCE BILL, 1955—*continued*

श्रीमती सावित्री देवी निगम : (उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, कल एबडक्टेड परसंस (रिकवरी ऐण्ड रेस्टोरेशन) कंटिनुएंस बिल का समर्थन करते हुये में यह कह रही थी कि यह समस्या बड़ी गम्भीर है और इस पर हम लोगों को बड़ी सावधानी से विचार करना चाहियें । जहां यह बात सच है कि हमें सेंटीमेंटल ग्राउण्ड्स पर कोई निर्णय नहीं देना चाहियें वहां यह बात भी सच है कि हमें प्रिजुडिमेंज के आधार पर या र्यूमर्स के आधार पर कोई ऐसा निर्णय नहीं देना चाहिये कि यह विभाग बिल्कुल बेकार या निकम्मा है । ऐसे मामलों में हमें शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण रख कर ही विचार करना चाहिये । यह में जरूर कहना चाहूंगी कि मानवीय दृष्टिकोण की संज्ञा कई लोग इसको भी दे सकते हैं कि रिकवर्ड स्त्रियों के मामले में उनके ऊपर होने वाले जुल्मों की कहानियां बिना सुने हुये, उन मांओं से बिना मिले हुये जिनके कि बच्चे या बच्चियां दूसरी ओर रह गई हैं या और घर के, परिवार के लोग दूसरी ओर रह गये हैं, हम यों ही बैठे बैठे अपने आप सिफ़ारिश कर बैठें कि यह विभाग बन्द कर दिया जाये । मेरी समझ में यह मानवीय दृष्टिकोण नहीं है । जब कभी ऐसी समस्याओं पर हम विचार करें तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम यह महसूस करें कि यदि हम स्वयं सफरर होते, यदि हम स्वयं आज इस स्थिति में होते जिसमें कि अभागी स्त्रियां हैं तो हमारी क्या स्थिति होती ? यदि किसी स्त्री का कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई भी दूसरी ओर दूसरे देश में है जिसको उसको कोई खबर नहीं मिलती तो क्या कोई भी स्त्री यह इमेजिन कर सकती है कि वह कभी इस विभाग को बन्द करने की सिफारिश कर सकेगी । मैं तो सोचती हूं

कि ऐसी स्थिति में उसका निर्णय बिल्कुल उसके विरुद्ध ही हो जायेगा ।

श्रीमान्, यह समस्या ८ वर्ष पूर्व उपस्थित हुई थी । लगभग ५० हज़ार व्यक्तियों की समस्या का निपटारा करने का समझौता ८ वर्ष पूर्व किया गया था, जिन के बारे में दोनों देशों के निवासियों को कुछ भी पता नहीं था । यह उस दुखद कहानी के बाद हुआ था जब कि इन्सान एक हैवान बन चुका था, जब कि बुरे से बुरे कृत्य किये गये, खेत जलाये गये, धन लूटा गया, बस्तियां बर्बाद की गई, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि इनको लोग भुला सकते हैं । धन का नुक़सान, ज़मीन का नुक़सान और और सब तरह के नुक़सान भुलाये जा सकते हैं पर सब कुछ खोने पर भी अपने प्रियजनों का बिछोह इन्सान के लिये इतना बड़ा सदमा दिलाने वाला होता है, इतना बड़ा दुख दिलाने वाला होता है कि उसका ज़ख्म, उसका घाव, कभी भी अच्छा नहीं होता, जब तक कि वह व्यक्ति जीवित रहता है, और विशेषकर उन प्रियजनों का बिछोह, जो कि अपमानजनक स्थिति में हों— वह तो बिल्कुल असह्य हो हो जाता है । इस कलंक को धोने के लिये भारत के रिकवरी विभाग ने जो तत्परता दिखाई और २०,६२२ आदमियों को निकालने का जो सराहनीय काम किया वह बड़ा ही स्तुत्य और अनुकरणीय है और मैं सोचती हूं कि पाकिस्तान के रिकवरी विभाग को भी भारत के रिकवरी विभाग के उन उपायों को अपनाना चाहिये जिनसे कि इतनी सफलता मिली है ।

यह सब बात तो मेरी समझ में आती है कि हम लोग अधिक से अधिक इस बात का प्रयत्न करें कि उस देश में भी जो हमारे बिछुड़े हुये बच्चे और बहनें हैं उनका हम पता लगायें । लेकिन यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती कि यदि उन लोगों ने तत्परता नहीं दिखाई तो हम लोग भी अपने इस मानवीय कार्य में जो अत्यन्त सराहनीय है, कोई ढिलाई लायें । एक शंका मेरे मन में बार बार उठती है कि यह काम उतनी सफलता से नहीं हो सका है जितना कि होना चाहिये था । उसका सब से बड़ा कारण यह है कि बार बार इस विधेयक की अवधि थोड़े थोड़े दिन के लिये बढ़ाई जाती है, जिससे ऐसा होता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनके मन में बराबर यह बड़ी शंका बनी रहती है कि अरे, यह थोड़े दिन की टेंपोरेरी चीज है, इसमें क्या फायदा है, क्यों इसके लिये इतनी ज्यादा कोशिश या प्रयत्न किया जाये ? इसलिये यह कहीं अच्छा होता कि यह विधेयक पहले ही अन्दाज़ा कर के काफ़ी समय के लिये लागू कर दिया जाता, इसकी अवधि पहले से ही बढ़ा कर कम से कम ७—८ वर्षों के लिये कर दी जाती । लेकिन अब भी मैं कहती हूं कि एक वर्ष की जो अवधि बढ़ाई गई है यह बहुत थोड़ी है, अच्छा हो यदि उसे बढ़ा कर सन् १९५८ तक के लिये कर दिया जाये । जब दोनों देशों में अपहृत व्यक्तियों की रिकवरी हो जाती है, उसके बाद भी उन्हें रिहैबिलिटेट करने की समस्या, या उनके बारे में पूरा-पूरा पता लगाना कि आया वे निवासी जो दूसरे देशों में चले गये हैं या बचा लिये गये हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका लालन पालन, निगरानी आदि ठीक से हो रही है, आदि बहुत से काम होते हैं । इनके कारण रिकवरी डिपार्टमेंट का जो काम है लोगों को रिकवर करना, सिर्फ उसी तक ही सीमित नहीं रह जाता । इसलिये मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस प्रश्न पर ज़रूर ही विचार करें कि इस बिल को १९५८ या १९५९ तक के लिये अवश्य बढ़ाया जाये ।

जैसा कि कुछ रयूमर्स सुनने में आती है, मुमकिन है वन परसेंट उसमें से सही भी हो, कि वे बहिन जो कि नहीं जाना चाहतीं उनको भी जबरदस्ती दूसरे देश में भेजा जाता है

[श्रीमती सावित्री देवी निगम]

या उनकी बातों की सुनवाई नहीं होती, तो ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिये एक सबसे अच्छा उपाय यह हो सकता है कि उसमें अधिक से अधिक समाजसेवियों का सहयोग लिया जाय और विशेष रूप से स्त्रियों का सहयोग लिया जाय ताकि एक भी ऐसा केस न होने पावे कि कोई स्त्री मजबूरी दरजे भेजी जाय उस देश में जहां वे एबडक्टर्स के पास हों और वहीं रहने के लिये इच्छुक हों। यह मामला कुछ ऐसा है कि इसमें हर एक केस को उसके मेरिट के अनुसार सोचने पर ही निर्णय दिया जा सकता है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि जो भी कमेटियां इस निर्णय के लिये बनाई गई हैं उनमें अधिक से अधिक समाज-सेवियों और स्त्रियों को शामिल किया जाय।

बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रिकवरी विभाग द्वारा किये हुये काम की धीमी प्रगति के बारे में बहुत शिकायत है, और यह शिकायत किन्हीं अंशों तक सही भी है। इसके लिये यही हो सकता है कि हम लोग नये-नये उपाय उन लोगों को सुझावें, और हर तरह से उन पर प्रभाव डाल कर, उन्हें प्रेरणा दे कर अधिक से अधिक इस बात की कोशिश करें कि वे लोग इस काम की प्रगति में कुछ तत्परता लावें, और तीव्र प्रगति लावें। लेकिन हमें भूल कर भी इस बात का इशारा नहीं करना चाहिये कि चूंकि पाकिस्तान में रिकवरी विभाग की प्रगति धीमी है इसलिये हम अपने विभाग को बन्द कर दें। जैसा कि मैं ने बताया, यदि हम समाज-सेवियों का अधिक से अधिक सहयोग लेंगे और इस देश और उस देश के समाज-सेवी उन कान्फरेंसेज में, जैसी कि कांफरेंस अब की बार हुई है और अगले वर्ष से बुलाई जाया करेंगी, मिल जुल कर, आपस में बैठ कर, उन उपायों का पता लगायेंगे जिनसे अधिक सफलता मिल सकती है, तो मैं सोचती हूं कि पाकिस्तान में भी कामयाबी हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं तो यह भी अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री महोदय से कि इस प्रकार की कांफरेंस हर साल बुलाई जाये, उसमें दोनों देशों के रिकवरी विभाग के कार्यकर्ता होने चाहियें, दोनों देशों के वे समाज-सेवी होने चाहियें जो कि रिकवरी विभाग को मदद दे सकते हों। उसमें ऐसी-ऐसी योजनायें बराबर बनाई जानी चाहियें कि किस प्रकार से रिकवरी विभाग के कार्य को अत्यधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एक और बात यह अवश्य होनी चाहिये कि उन कार्यकर्ताओं को जो बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये तत्परतापूर्वक उस काम को कर रहे हैं दोनों देशों में मेडल वगैरा देकर सम्मानित किया जाना चाहिये। कुछ न कुछ इंसेंटिव लोगों में क्रिएट किया जाना चाहिये जिससे वे और ज्यादा तत्परता से काम करें क्योंकि यह एक बड़ा मुश्किल काम है। रिकवरी विभाग के कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय रह चुका है और मैं जानती हूं कि उनको इतनी अधिक कठिनाई पड़ती है इन कामों के करने में कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर हम उन लोगों का साहस बढ़ाने के लिये ऐसी बातें करें जिनसे उनको अच्छा काम करने के लिये कुछ पुरस्कार भी दिया जाय तो मैं सोचती हूं कि उनका उत्साह और अधिक बढ़ेगा और कार्य में भी और अधिक सफलता मिलेगी।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

श्रीमान्, मैं भी बच्चों के बारे में बहुत चिन्तित हूं क्योंकि बहुत से केसेज में ऐसा भी हो सकता है कि मातृ प्रेम से वशीभूत हो कर अपने जिन नन्हें बच्चों को अपने निजी देश में ले जायें, बाद में जा कर उन बच्चों की स्थिति उस परिवार में वैसी न रहती हो जैसी कि स्वाभाविक रूप से होनी चाहिये और मां को भी अपने परिवार वालों के प्रभाव

में आकर मजबूर होना पड़ता हो जिससे बच्चे को उतना टेंडर केयर न मिल पाता हो जितना कि एक बच्चे को अपनी मां से मिलना चाहिये । ऐसी स्थिति में मेरा यह विचार है कि जो मायें अपने साथ बच्चों को ले जाती हैं उनका भी लेखा-ब्यौरा रखने के लिये एक शिशु विभाग विशेषकर रिकवरी विभाग में बनाया जाय जिसके कार्यकर्ता वर्ष भर में दो तीन बार सरप्राइज विजिट देकर उन बच्चों का हाल मालूम करें जो कि अपनी मांओं के साथ दूसरे देश में चले गये हैं । वे बच्चों की ठीक ठीक स्थिति का पूरा पूरा पता लगावें और मांओं से मिल कर बातचीत करें और यह पता लगावें कि आया वे बच्चे उस मां के लिये बोझ तो नहीं बन गये । वे यह भी मालूम करें कि परिवार में उस बच्चे की स्थिति को खराब करने वाली कोई बात तो नहीं है ।

मुझे रिकवरी विभाग में एक त्रुटि और प्रतीत होती है जिसको मैं यहां कह देना चाहती हूं । वह है उसकी वर्किंग के सम्बन्ध में । आम जनता को तो जाने दीजिये, हम संसद् सदस्यों को भी रिकवरी विभाग की वर्किंग से इतना अपरिचित सा रखा जाता है कि हमें कुछ पता नहीं चलता कि वहां क्या हो रहा है । यही कारण है कि हमारी बड़ी योग्य बहिनें भी इस विभाग के बारे में ऐसी ओपीनियन, अनभिज्ञता के कारण, फॉर्म कर लेती हैं जैसा कि हम सुन चुके हैं । इस विभाग का पूरा-पूरा लेखा-ब्यौरा, उन स्त्रियों का पूरा-पूरा पता जो दूसरे देशों से रिकवर की जाती हैं, दिया जाना चाहिये । यदि ऐसी स्त्रियों का पूरा पूरा पता जो बिचारी वहां से बचा कर लाई गई, जिनको एक एक पल अपने उन एबडक्टर्स के हाथों पड़ कर काटना मुश्किल था, दिया जाता और उनके बयानात एक बुकलेट के फॉर्म में हमारे सम्बन्ध को सर्कुलेट किये जाते तो मैं समझती हूं कि यह अस्वाभाविक स्थिति कभी पैदा नहीं होती कि हम कोई एकतरफ़ा ओपीनियन फॉर्म कर लेते । इसलिये मैं अनुरोध करूंगी कि अगर अब तक यह चीज नहीं हुई है तो आगे कोई ऐसा मेथड निकाला जाय जिससे पूरा लेखा-ब्यौरा कम से कम संसद् सदस्यों को तो मालूम हो और उनको पूरी-पूरी जानकारी हासिल हो सके कि कितने लोग आये हैं, कितने लोगों की एप्लिकेशन्स आने के लिये आई हैं, उनमें कितने बच्चे, लड़के लड़कियां और स्त्रियां हैं, आदि ।

जैसा कि मैं ने भी कहा, मैं बच्चों के बारे में बड़ी चिन्तित हूं । मैं चाहती हूं कि दोनों देशों में जो बच्चे इस तरह ले जाये गये उनकी निगरानी के लिये दोनों देशों में होम्स जरूर बनाये जाने चाहिये जिनमें बच्चों की उचित शिक्षा और उच्च शिक्षा का भी पूरा-पूरा प्रबन्ध हो । जब बच्चे नन्हें होते हैं तब तो वे अपने सौतेले पिता के घर में जा कर भी परिवार वालों का प्रेम पा लेते हैं, क्योंकि नन्हें बच्चे यूंही प्यारे होते हैं, लेकिन जब बड़े होने पर उनको वह निगरानी न मिल पाती हो जैसी कि मिलनी चाहिये तो उस दशा में उन्हें ऐसे होम्स में रख कर उनकी शिक्षा-दीक्षा की जा सकती है और उनका भविष्य सुन्दर तरीके से बनाया जा सकता है । एक दलील यह भी दी गई कि बच्चों की दशा बड़ी करुणाजनक हो जाती है और वे डेलिक्वेंट बन जाते हैं जब वे दूसरे देशों में जाते हैं । पर एक दो दिन पहले मैं चाइल्ड डेलिक्वेंसी पर एक किताब पढ़ रही थी, उसमें इस विषय पर सर्वे किये गये फिगर्स दिये हुये हैं । उसमें यह बतलाया गया था कि किस तरह के बच्चे सबसे ज्यादा डेलिक्वेंट बन जाते हैं । उसमें साफ साफ बताया गया था कि वे बच्चे डेलिक्वेंट बन जाते हैं जिनके घरों में मां-बाप के बीच पारिवारिक कलह

[श्रीमती सावित्री देवी निगम]

रहता है, अर्थात् लड़ाई-झगड़ा, कोहराम की वजह से हमेशा एट्मौसफेयर खराब रहता है। इसलिये, यदि उस स्त्री के ऊपर, जो अपने एबडक्टर के साथ रह रही है, जुल्म हो रहा है, और लड़ाई-झगड़ा, और ज्यादती का उसके परिवार में जोर है तो उसमें बच्चे की स्थिति सुधरती नहीं है बल्कि और ज्यादा बिगड़ती है। वहां उसके डेलिक्वेंट होने के ज्यादा चांसेज हैं बनिस्बत इसके कि उसको एक होम में रख दिया जाय या किसी योग्य शिक्षक के पास रख दिया जाय। उस हालत में उसकी स्थिति कहीं अधिक सुधर जायगी।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल (उत्तर-प्रदेश): ज्यादातर बच्चे तो यूं ही छोड़ दिये जाते हैं।

श्रीमती सावित्री देवी निगम: श्रीमन्, मैं सोचती हूं कि जो बच्चे छोड़ दिये जाते हैं उनकी स्थिति भी अभी उन बच्चों से कुछ अच्छी है जो बच्चे कि मां बाप की ज्यादतियों, अत्याचार और कलहपूर्ण वातावरण के बीच में रहते हैं क्योंकि लड़ाई-झगड़े का जो प्रभाव है वह उनको और ज्यादा डेलिक्वेंट बना देता है। चाइल्ड डेलिक्वेंसी के बारे में जो रिपोर्ट है उसमें डिज़र्टेड चिल्ड्रेन के बारे में नहीं लिखा है, आरफेंस के बारे में नहीं लिखा है बल्कि उसमें इस बात पर साफ साफ जोर दिया गया है कि जिन परिवारों का एट्मॉस्फेयर ज्यादा खराब रहता है वहीं के बच्चे ज्यादातर डेलिक्वेंट बन जाते हैं। इसलिये श्रीमन् वह दलील भी कोई ठीक नहीं प्रतीत होती। यदि दोनों देशों के निवासी उन बच्चों को होम्स में रख कर उनका अच्छे तरीके से लालन पालन करें तो मैं सोचती हूं कि उनके डेलिक्वेंट बनने के चांसेज नहीं हो सकते। हम लोगों ने देखा है कि सैकड़ों रिफ्यूजी बच्चे रिफ्यूजी होम्स में रहते हैं और बहुत ही सुन्दर तरीके से उनकी शिक्षा हो रही है। जब इन बच्चों को रिफ्यूजी होम्स में हम देखते हैं तो यह मालूम पड़ता है कि इनका हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा अच्छी तरह से विकास हो रहा है और योग्य शिक्षकों की निगरानी में रह कर वे शिक्षा पा रहे हैं।

एक बात बहुत ही आवश्यक है और वह यह है कि जो स्त्री सात और आठ वर्ष के बाद दूसरे देश से बचा कर लाई जाती है तो दोनों देशों में उसको हर प्रकार का लीगल स्टेटस और हर प्रकार का सरकारी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था हमें विशेष रूप से उनके क्लेम्स वगैरा के सम्बन्ध में और रिफ्यूजियों को जो भी बेनिफिट्स मिलते हों, उन के सम्बन्ध में करनी चाहिये। एक बात यहां पर विशेष ध्यान देने योग्य है कि इस तरह की औरतें जो आती हैं वे उस तारीख के बाद आती हैं जो कि रिफ्यूजियों के क्लेम फाइल करने की अन्तिम तारीख होती है, वे उस तारीख के बीत जाने के बाद आती हैं और वे अपना क्लेम फाइल नहीं कर सकतीं। इसलिये मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस तरह की जो औरतें आती हैं उनको भी वही लीगल स्टेटस दिया जाना चाहिये जो कि उस तारीख के भीतर आने वालों को मिला हुआ है। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई और उनको रिफ्यूजी बेनिफिट्स नहीं दिये गये तो इस तरह के लोग जो क्लेम्स की तारीख के बाद आयेंगे वे और अधिक कठिनाई में पड़ जायेंगे। मेरे पास एक दो केसेज ऐसे आये हैं जिनमें दो स्त्रियों को जो कि एबडक्टर्स के पास थीं और वहां से बचा कर यहां लाई गई थीं, यहां उनके घर में कमाने वाला या परवरिश करने वाला कोई नहीं था। उनको अपने क्लेम्स फाइल करने में काफी दिक्कत उठानी पड़ी। अगर सरकार की ओर से यह प्रबन्ध

कर दिया जाता है कि इस तरह के लोगों को रियूजी बेनिफिट्स और लीगल स्टेटस दिया जायेगा तो वहां से लोग आने के लिये अधिक रजामन्द हो जायेंगे । जब लोगों को मालूम होगा कि उनको इस प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं तो उनके मन में यहां आने के लिये किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी । जो ऐसी बहिनें हैं, जिनके केसेस फाइल नहीं हो सकते हैं, जिनके घर के अन्दर कोई सीनियर अर्निंग मेम्बर नहीं है उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार को उठा लेनी चाहिये क्योंकि सिर्फ भरण-पोषण के लालच से कोई स्त्री विदेशों में एक एबडक्टर के पास रहने पर मजबूर हो, यह स्थिति देश के लिये बड़ी अपमानजनक है और हम सब के लिये भी अपमानजनक है । जब कोई स्त्री अपने पालन-पोषण के लिये अपने देश जाना चाहती हो किन्तु वहां पर उसका उचित तरीके से पालन-पोषण सम्भव न हो, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होना सम्भव न हो और इन कारणों से वह एबडक्टर के साथ रहने के लिये मजबूर होती हो, तो इस तरह की स्थिति हमारे देश के लिये लज्जास्पद होगी । इसलिये मैं चाहती हूं कि इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं, जो यहां आना चाहती हैं, जिनके यहां कोई अर्निंग मेम्बर नहीं हैं, उनकी सारी लायबिलीटी सरकार उठाये और उनकी शिक्षा-दीक्षा और भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले ।

इसके बाद, मैं एक बार फिर पूरी तरह से इस बिल का समर्थन करती हूं और सरकार से अनुरोध करती हूं कि कम से कम इस विधेयक की अवधि दो वर्ष के लिये यानी सन् १९५८-५९ तक तो जरूर बढ़ा दी जाये । यदि अब की बार इतनी नहीं बढ़ाई जा सकती तो अगली बार अवश्य बढ़ा दी जाय । जब तक इस तरह की एक भी स्त्री दोनों देशों में से किसी भी देश में रह गई हो और वह जुल्म व सितम से पीसी जाती हो तब तक इस रिकवरी विभाग को कायम रखा जाना चाहिये । मैं सोचती हूं कि अगर हमने ऐसा किया तो यह बहुत ही मानवीय और बहुत ही उचित स्टेप होगा । धन्यवाद ।

PROF. A. R. WADIA (Nomina ted >: Mr. Deputy Chairman, I am sure we would all wish triac the need for thi* Bill did not exist. But considering the situation as it is we cannot but support wholeheartedly the Bill that has just been introduced in connection with the abducted women. I listened to the speech of Shrimati Lakhanpal yesterday with very great interest. I admire her boldness and I do know that she represents a fairly widespread opinion in the country that the time has perhaps arrived or must soon arrive when this desire to hunt up the abducted women should cease so that the agony may not be protracted, and a full opportunity may be given to the abducted women on both sides somehow to settle down in their new surroundings. But considering that these abducted women were the unwilling victims of the passions that were most unexpectedly aroused at the time of our independence and considering the hardships to which they and their families had been subjected, it stands to reason that the Governments concerned have a dutj' of finding out these abducted women; and if they wish to go back to their original countries, it is the duty of the Government to give a helping hand in this respect.

I am afraid the speech of Shrimati Savitry Devi Nigam goes to the other extreme. She feels that under no circumstances should an abducted woman be allowed to continue in her new surroundings. She feels that it is an outrage on the part of a woman to continue to be with her abductor all her life. I am afraid this is I also an extreme view. After all, ! an abductor is also a human being

[Prof. A. R. Wadia.] and whatever may have been his lap ses at the time of abduction, he may-have proved his humanity in coming years and may have taken the ab ducted woman to his heart, given her a home, and brought up a family. If in the circumstances an abducted woman chooses to continue in the new environment...............

SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM: What about those who are still being oppressed by the abductors?

. A. K. WADIA: I am coming to that. I am talking of these who 1 been willingly taken up. In such cases I think it would be rather unfair to root them up from their new surroundings. But the unfortunate fact remains that the majority of the abducted women still continue in a very unhappy condition, and it is in their interest that the Government should do what they can to reclaim them. In this little brochure which was published by both the Governments in 1952, I was interested to read:

> "To our knowledge only two cases of Hindu girls have returned to Pakistan and four Muslim persons have returned to India out of 16,919 that were transferred to Pakistan for restoration to their relatives and 8326 that were sent to India for the same purpose."

Well, these figures are quite revelatory in their own way. The correct view is that since a wrong has been done, it is the duty of the Government to do all they can to find out the whereabouts of these abducted women, to get in touch with them, jiid to find out what their real wishes are. And I am glad that both the Government of India and the Government of Pakistan have been very honest in this endeavour. They are conscious of the guilt to which these unfortunate women were exposed and I am glad that with a noble band of honorary workers both in India and in Pakistan, a good deal of fine work has been achieved. A good many of these lost women have been found out. All of them have been given more or less a chance to meet their relatives and if they wish to go back, an open invitation has been held out to them to go back to their own families in their own countries. I think nothing else than this can any responsible Government do. And it is for that reason that I congratulate Sardar Swaran Singh on the spirit in which he has introduced this Bill and the spirit in which the Government are carrying on their work.

It is interesting to find that in spite of this terrible catastrophe, sflkne-thing good has come out. One good I have already mentioned that some abductors have been found to be satisfactory. That is some compliment to-human nature that it is not entirely bad. There might have been a very honest doubt on the part of many abducted women—I may be pardoned if I say, especially ,among the Hindu women—whether they would ever be received back by their families. Knowing as we do the great strength of the caste system in this country, I am perfectly certain that about 5(1 years ago if this sort of thing had happened, I am afraid, these women would not have been received back into their families. But it speaks a good deal of the new India that is being born before our very eyes that a huge majority of the Hindu families have expressed their willingness to take back their daughters and to take back their old wives$_r$ even with the children of their Muslim abductor husbands. It speaks a good deal for human nature, and it speaks a good deal for the refined spirit that we find in the Hindu society today that this spirit has manifested itself, and it is this spirit which has made it possible for many of these Hindu abducted women to choose to come back to their own country. In some cases where tnese abducted women 'ire willing to come

back, but where their families are not willing to take them back, and they do not find their position in their new country very satisfactory, I am very happy to find that both' the Governments have been prepared to take up the responsibility of looking after the abducted and to give them a new chance to settle down in their own country, maybe, by teaching them some craft, maybe, by enabling them to marry afresh, or in some such way to find a new home in their own country, even though it may not be in their own family.

Recently, Sir, i have been in touch with the Recovery Department, and some very interesting facts have been brought to my notice, and I should like to share them with the Members of this House. It is interesting to find how many Indians are willing to marry such women, even though they are not accepted by their own families. I am told that enquiries come from Indian genile-m ;n in places as far as Nairobi, East Africa enquiring whether there are such women who would be prepared to go to Africa and get married to them. It speaks well of human nature again. We have all been very painfully aware that many of these abducted women have been forced into prostitution. Cases have been on record where a woman has passed through as many as eight or nine hands. One would imagine that they would be doomed for ever. And yet, I have been happy to find that even in this city of Delhi, honourable men, with a sense of responsibility and with a sense of generosity, have come forward to marry these women, and the prostitutes of yesterday have been enabled to become honourable wives of today. Again. Sir, it speaks well of human nature.

It has also been found that even ^though some children have been born under conditions for which the mothers were not responsible, the maternal instinct has asserted itself, and the mothers have been taking very kindly to their children. In many cases they have refused to give no up, even though it has meant a good deal of hardship to themselves. In several cases, mothers have been persuaded to accept that it is in their interest and in the interest of their children, if the children are allowed to be brought up by the State. And I am glad, Sir. that both the Governments have accepted the responsibility of bringing up these unfortunate children. Now here again. I am very happy to find that a new spirit has been entering into the Hindu society.

We are all familiar with the principle of adoption in Hindu Law, and we all know the rigid limits within which that adoption had to be prac-tised. But today we find that some childless parents have willingly come forward to adopt these abandoned children who have been brought up by the State, knowing full well that their mothers were Hindus but their fathers were Muslims. Again it is a compliment to human nature. I am glad that this catastrophe has made it possible for some new features to come into existence in our society.

Well. Sir, it is a very hard task to find out these lost women. I am tolcl that very often, out of the six women that have been discovered, only one name had been registered, and even that one name had been possibly registered under six different names, as Sardar Swaran Singh made it clear yesterday. There are women who were not on the registered list, but through some lucky chance, they got in contact with the different agencies in both the countries and ultimately they were declared to be abducted women who were willing to go back to their own country. How long this state of things will exist, it is impossible for any Government to know. The Government accepted an amendment in the other House to the effect that this measure

[Prof. A. R. Wadia.] should continue till the 30th of November 1956. I am not optimistic-enough to believe that this problem will be solved in that short time. Perhaps, there is some justification for what Mrs. Nigam has just said ! that there might be need for the ' extension of this Act for a year or even more. It is a very sad state of affairs, but lacing the situation as we j do what else can we do? What else ! can we expect the Government to do? I am afraid, it will be impossible to account for every woman that has been abducted in either country. But in so far as we have got the names of abducted women on either side, I \ am afraid, it will be the duty of the Government to do their very best to find them out and at least to give them a chance to say whether they would like to continue in their new surroundings or whether they would like to come back. That is the minimum that we can expect any civilised Government to do: and especially when we find that our society is also becoming very civilised, very generous, and very new-minded j in its attitude, I am afraid, this measure .will have to continue for some time at least. We may deplore it but it is a necessity. Well, Sir, I congratulate the Government and the band of social workers who have been helping the Government in solving this tremendous problem. That is why I whole-heartedly support this Bill.

سردار بدھ سنگھ (جموں اور کشمیر) : جناب ڈپٹی چیرمین صاحب ! یہ جو بل ہاؤس کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے متعلق ۱۳ دسمبر سنہ ۱۹۵۲ کو میں اپنے خیالات مفصل طور پر بیان کر چکا ہوں- اور آنریبل موور آنریبل سردار سورن سنگھ نے مفصل وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں اس کی ضرورت ہے - اب اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی دو رائے ہی ہو سکتی ہیں ؟ آیا اس کام کو جاری رکھنا چاہیئے یا نہیں - میں جموں اور کشمیر کے نمایندے کے ناطے ۱۳ دسمبر سنہ ۱۹۵۲ کی اسپیچ میں اس کے متعلق بہت کچھ کہہ چکا ہوں - آج صرف میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک معمولی سوال نہیں ہے اور ایک آرڈنری سوال ٹریڈ کا لین دین کا یا اور کسی قسم کے دونوں گورنمنٹوں کے درمیان ایگریمنٹ کا نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک کی ان ہزاروں عورتوں، بیواؤں، بوڑھوں اور جوانوں کی زندگی اور عزت کا ہے جنکو کہ جبراً لیجایا گیا ہے - دونوں پنجاب کی صورت تو الگ ہے لیکن جموں اور کشمیر میں ہزارہا کی تعداد میں قبائلیوں کے نام پر پاکستانی سپاہی اور فوج کے لوگ باقاعدہ توپ اور بندوق کے ساتھ گھس آئے اور حملہ کیا - اور نہ صرف وہاں سے ہزاروں ایسے آدمیوں اور عورتوں کو لے گئے بلکہ ایسا خلاف انسانیت کام کیا کہ جس سے بڑی شرم آتی ہے ، اور ہمیں رنج ہوتا ہے اور ہم خون کے آنسو روتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ان کو وہاں تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بیچا گیا ، ان کی عصمت دری کی گئی اور بڑے بڑے کیمپ کھول کر ان کو بھیڑ بکری کی طرح روک

رکھا گیا - جموں اسٹیٹ میں میرپور کے پاس ایک علی بیگ کیمپ کھولا گیا اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں جتنے جوان تھے وہ سب قتل کئے گئے، کئی بچے بھی قتل کئے گئے اور عورتوں کو وہاں سے لے گئے - اس وقت تک گورنمنٹ نے یہ تعداد دریافت نہیں کی کہ ہمارے ملک کے کتنے لوگ اب بھی ان کی قید میں ہیں - یہ دوسری بات ہے کہ یہاں کافی بحث و تحقیقات ہو رہی ہے کہ کون اور کتنی عورتیں ایبڈکیٹڈ ہیں اور ان کو کہاں بسایا گیا ہے لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے لوگ پاکستان کے ان کیمپوں میں بند ہیں جو کہ اپنے ملک کو آنے کے لئے تڑپ رہے ہیں - وہ بیچارے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے اور ہندوستان کی بڑی شان ہے، بڑا وقار ہے، وہاں ۳۵-۳۶ کروڑ لوگ بستے ہیں ان کی اخلاقی، مالی اور ہر قسم کی ہمیں مدد مل سکتی ہے اور فوج طاقتور ہے جس کے لئے اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو ہم اس کا پورا مقابلہ کریں گے - اتنی بڑی شان و وقار کا ہندوستان اور اس فوج اور طاقت اور جنتا کی مدد ہونے کے باوجود بھی اتنے معصوم بچے اور بے گناہ مظلوم عورتیں اور لوگ ابتک پاکستان کی قید میں ہیں کتنے رنج کی بات ہے -

بیشک یہ ملک مہاتما گاندھی کا ہے جہاں امن و شانتی سے کام ہونا چاہیئے - بیشک یہاں کی روایات بہت اونچی ہیں - بہت مبارک ہے - یہاں کی تہذیب اور اخلاق بلند ہیں - یہاں کی تاریخ دیکھئے ایک سیتاجی کی قید کا یہاں کیا نتیجہ نکلا - تمام لنکا ختم ہو گئی، تمام ہندوستان میں غم و غصہ کی آگ بھڑک اٹھی اسکو واپس لانے کے لئے - درویدی کا چیر ہرن ہوا اسکو بے عزت کیا گیا جس کے لئے کوروں اور پانڈوں میں کورکشیتر کے میدان میں جنگ ہوئی اور ان سے پورا مہابھارت اور رامائن بھرا ہوا ہے - لیکن اب صورت مختلف ہے تو جیسا میں نے عرض کیا کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی سبھیتا، اس ملک کی تہذیب، سنسکرتی، اخلاق کلچر، تمدن بہت اونچا ہے اور مہاتما گاندھی کا یہ ملک ہے - مہاتما بودھ کا ملک ہے اس لئے لڑائی جنگ نہیں کرنا ہے مگر اس کے لئے یہ بھی تو نہایت ضروری ہے کہ جبتک ایک بھی بچہ یا ایک بھی عورت ایسی ہے تب تک زبردست سے زبردست کوشش کرنی ہے - اور ہر ممکن طریق سے ان کو واپس لانا ہے اول گورنمنٹ کو اخلاقاً قانوناً ہر طرح سے بڑی

[سردار بدھ سنگھ]

کوشش کرنی چاہیئے کہ جو ادھر کے ایسے لوگ یہاں کہیں ہیں ان کو تلاش کر کے نکالا جائے اور ان سے پوچھ کر وہاں اپنے سمبندھیوں کے پاس بھیجدیا جائے اور سرخرو ہوں - جب یہ ہو جائے گا تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ آیا ایک غیرت مند قوم ، طاقتور قوم - اور وقار رکھنے والی قوم کا آگے کیا فرض ہے - ان معصوم مظلوم ہستیوں کو چھڑانے کے بارے میں ہمارے غریب ملک ، پسماندہ ملک ، پہاڑ کے ملک اور ہمالیہ کے پہاڑوں کے نیچے رہنے والے لوگوں کے معصوم بچوں اور عورتوں کو جبراً حملہ آور لے گئے ہیں ان کی بابت بھی فکر کرنا ہے اور ابھی سے سوچنا ہے ان کے لئے کیا آخری قدم اٹھایا جائے دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے - یہ کیا امن و صلح کی باتیں ہیں - میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی ہسٹری ایسی باتوں سے بھری ہوئی ہے کہ کسی طاقتور ملک یا کسی یورپین ملک کی ایک عورت کو کوئی لیجاتا ہے قید کرتا ہے یا مار دیتا ہے تو جنگ شروع ہو جاتی ہے اور لاکھوں آدمیوں کا خون ہو جاتا ہے - لیکن ہم ایک اصول کو بنائے ہوئے ہیں کہ جنگ نہیں کرنا - بیشک آپ اصول کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے کشمیر رہے یا نہ رہے ہندوستان رہے، یا نہ رہے - واقعی اصول و آدرش پر قائم رہنا چاہیئے - یہ ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سمجھوتہ کس سے کیا جائے - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں - کس کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں - میں نے کئی بار کہا ہے کہ جو شخص بدنیت ہے ، بے ایمان ہے ، جھوٹا ہے ، بے رحم ہے اس کا کیا بھروسہ - ایک طرف بے ایمانی ہے ، فریب ہے دھوکہ ہے ، وحشت و درندگی ہے اور ایک طرف امن ، شانتی و صلح کا سوال ہے - ایمانداری ہے ، تہذیب ہے ، اخلاق ہے ، اور ہمدردی سے ، پیار سے ، محبت سے بات چیت کر کے معاملہ طے کیا جاتا ہے - ٹھیک ہے ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے دیکھیئے ایک ہماری بہن نے کہہ دیا کہ اس بل کی ضرورت ہی نہیں - کسی نے اس کو گھما کر کہدیا کہ اس میں یہ نقص ہے - وہ نقص ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ انسانی ہمدردی - عزت - غیرت و وقار کا سوال ہے - جموں و کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن ہو گیا ہے ، قطعی الحاق ہو گیا ہے - نیشنل کانفرنس کی آرگنائزیشن نے اور کشمیر کے نمائندوں نے آئین ساز اسمبلی میں فیصلہ کر دیا ہے - ایک دفعہ نہیں بار بار سنہ ۱۹۴۸ میں ، ۴۹ میں ، ۵۰ میں ، ۵۲ میں ، ۵۳ میں اور ۵۴ میں ۵-۱

سال متواتر هم یه ریزولیشن پاس کرتے رهے هیں که همارا الحاق هندوستان کے ساتھ هو چکا هے - اس لئے جب تک سیز فائر لائن کا مسئله حل نهیں هوتا جب تک وه ملک کا حصه همارا واپس نهیں آتا اور جب تک همارے بچے عورتیں یا بهنیں اور مائیں وهاں سے نهیں لائی جاتی هیں تب تک میں کهوں گا که یه سلسله تلاش و برآمدگی کا برابر چلنا چاهیئے - جهاں لاکهوں کروڑوں روپیه هم فائیو ایر پلان میں خرچ کر رهے هیں تو پهر جب یهاں قوم کی ماؤں اور بهنوں کا مسئله هے ' غیرت اور عزت کا مسئله هے ' ملک کے وقار کا مسئله هے وهاں اس کے لئے آپ سوچتے هیں که کتنا روپیه خرچ کریں اور کتنا نه کریں - یه سارے هندوستان کی عزت کا سوال هے - ایک غریب ملک ایک اصول و آدرش کو لیکر آپکے ساتھ شامل هوا هے - اس نے اپنی قسمت کو آپکے حوالے کر دیا هے اور اپنا سب کچھ آپکے سپرد کر دیا هے : لیکن اس رنجیده مسئله کا حل باقی هے - میں دیکھتا هوں که جب ایک بل اسکے متعلق آیا هے تو اس پر غیر متعلقه طریقه پر گفتگو هوتی هے - جن کے آدمی مرے هیں - جن کے بچے وهاں هیں، جن کی ماں بهنوں کی عصمت دری هوئی هے اور جو تباه و برباد هو گئے هیں ان سے تو پوچھئے که آیا یه سلسله آگے چلنا چاهیئے یا نهیں، چلنا چاهیئے اور کسی حد تک چلنا چاهیئے - میں بار بار یه عرض کرنا چاهتا هوں که اگر جنگ نهیں کرنا هے تو پهر اب آگے اور کیا سلوشن ره جاتا هے - صرف بات چیت کا - کهاں تک منتیں کرتے رهیں گے؟ کهاں تک خوشامدیں کرتے رهیں گے؟ کهاں تک ایگریمنٹ کرتے رهیں گے ہم اپنے پنیهج پر قائم هیں - لیکن وه قائم نهیں هیں - تو پهر کیا هماری بهنیں وهیں رهیں گی - کیا وه کبهی آپائیں گی بهی یا نهیں یا صرف هندوستان کا نقشه دیکهیں گی اور اخباروں کو پڑهتی ، سنتی رهیں گی - کیا وه یهاں هندوستان کے وقار کو ' تهذیب کو ' فوج کو، توپوں اور بندوقوں کو اور سپاهیوں کو دیکهتی رهیں گی - اور یه کهیں گی که ان کے لئے دنیا میں کوئی مددگار اور سهارا نهیں رها - دنیا میں کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نهیں هے - کوئی ان کو ظلم سے، تشدد سے اور هر قسم کی زیادتیوں سے چهوڑانے والا نهیں هے - یه کتنی دردناک اور خطرناک بات هے -

همارا کشمیر کا مسئله بالکل مختلف هے - ڈپٹی منسٹر صاحب نے پچھلے دسمبر میں کها تها که یه سیاسی مسئله نهیں هے - یه اخلاقی هے - مگر همارا مسئله سیاسی

[سردار بدھ سنگھ]

بھی ہے اور اخلاقی بھی - دھرم کا بھی ہے سب کچھ ہے - اگر کسی کی لڑکی یا کسی کی عورت اغوا کی جائے اور اس کے اوپر دوسرے کسی شخص کی قید کے اندر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ساری پولیس حرکت میں آ جاتی ہے اور تلاش کیلئے بھیجی جاتی ہے - لوگ دوڑ پڑتے ہیں - پکار پکار کر چاروں طرف سے آواز اٹھتی ہے - حالانکہ وہ اپنے ملک میں ہی اغوا کی گئی ہے لیکن ہمارے یہاں شریمتی لکھن پال کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے کہ ن صاحب کوئی چاہے وہاں سے آ سکتا ہو یا نہ آ سکتا ہو ان عورتوں کو واپس لینا مشکل ہے - غرضیکہ ان کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش نہ کی جائے - ان پر یہ مصیبت نہیں آئی ، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ عورتیں کس طرح سے اپنے مصیبت و دکھ کے دن گزار رہی ہیں - میں کہتا ہوں کہ وہ قوم یا وہ ملک بڑا و عزت دار نہیں ہے جو اپنے بچوں کو ، اپنی عورتوں کو با عزت دوسرے ملک سے چھڑا نہیں لاتا اور اپنے پاس نہیں رکھتا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری طرف کی جو عورتیں و بچے جو دشمن کے قبضے میں زبردستی قید ، بند میں پڑے ہوئے ہیں ان پر جبر اور ظلم کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے - مگر ہم ان کے لئے خاطر خواہ کوشش نہیں کر سکے - مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کو واپس لانا چاہیئے اور عزت سے بسانا چاہیئے - آج مہاتما گاندھی ہوتے تو وہ ہر قربانی کرکے ان لڑکیوں کو ڈھونڈ نکالتے اور ان کو گلے سے لگا لیتے - لیکن یہ شرم اور غیرت کی بات ہے کہ ہم میں سے کئی اپنی بہنوں کو اپنے دھرم میں اور اپنے قوم میں لے لینے سے ہچکتے ہیں - اپنے ملک میں تو میو ، کرشچین کیطرح کئی قومیں ہیں جن میں سے کئی لوگوں کو آپ سدھی کر کے اپنے دھرم میں داخل کر لیتے ہیں لیکن کیا ان عورتوں اور بچوں کے لئے تمام دروازے بند ہیں - ہم سے پوچھو جن کے ساتھ یہ گزر رہی ہے - میرے اپنے خاندان کے نزدیکی بیس عورتیں آدمی مارے گئے - میرے اپنے کئی رشتہ دار چلے گئے - مجھے اپنے متعلق کچھ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا - میرا وطن ہندوستان میں شامل ہوا ہے لہذا اس کی فارن پالیسی سے ہمیں پورا اتفاق ہے اور اسی وجہ سے ہم تمام قربانی ، تمام تکلیفیں اور مصیبتیں ، ہر دکھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں - ہندوستان سلامت رہے ، اس کی عزت بنی رہے ، یہی ہم چاہتے ہیں - ورنہ ہم جانتے ہیں کہ جیسی صورت میں ہمارے اپنے لوگ پھنسے

ہوئے ہیں اس میں تو جنگ ہو جانی چاہیئے تھی - ہمارا ایک ایک ضور رسیدہ مرد و عورت کہتا ہے کہ جنگ ہو لڑو یا مرو یا ہمارے آدمی واپس لاؤ - ہم نے کہا کہ اتنے آدمی مارے گئے اور اگر ہم نے لڑائی چھیڑی تو ملک برباد ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا - دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اصول کو نہیں چھوڑ سکتے - ہم اپنے اصول اور آدرش پر قائم ہیں اور اسے ہم کسی حالت میں بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں - علاوہ ازیں ہمارے دس لاکھ آدمی وہاں رہ گئے ہیں - صرف ہندو یا سکھ بھائی ہی نہیں رہ گئے ہیں بلکہ بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی وہاں پر رہ گئے ہیں- ایک دو کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں - ان کے جو رشتہ دار یہاں پر ہیں ان کی مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ان کو زبردستی پکڑ کر لیجایا گیا ہے وہ تڑپ رہی ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں ان کے اوپر تشدد ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے - وہاں پر قتل و خون کیا جا رہا ہے اور ہمارے حصہ کے ملک میں کئی جگہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے - وہاں پر پاکستان کی پولیس اور فوج باقاعدہ قتل و خون کر رہی ہے اور وہاں کے لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور ہندوستان کی سرکار سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم کو بچاؤ ہماری حالت کو ٹھیک کرو -

SHRI KISHEN CHAND (Hyderabad): Is it all relevant to this question?

MR. HEFUTY CHAIRMAN: Let bin? continue.

سردار بدھ سنگھ : پاکستان کی اسمبلی کے علاوہ وہ لوگ ہندوستان سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہو سکتا ہے ہمکو بچاؤ - ادھر یہ ہو رہا ہے - مگر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کمٹمینٹ کیا ہے - میں ہند سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت جنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو لڑائی بندی ہوئی اس وقت کیا ہمارے جواہرلال جی نے کشمیر کے لوگوں سے یہ کمٹمنٹ نہیں کیا تھا کہ ہم ایک ایک انچ زمین اپنی واپس لیں گے - کیا یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب سب کچھہ ٹھیک ہو جائے گا ریڈرز کو بھگا دیا جائے گا تو ہم اپنی ساری زمین کو واپس لے لینگے - آج ہماری ریاست میں چار میل سے ۲۰۰ میل تک وہ لوگ گھس کر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں - اور ہمارے جو آدمی وہاں پر ہیں ان کے اوپر ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے - آپ سب لوگ اخباروں میں پڑھتے ہی ہوں گے کہ مظفرآباد اور میرپور کے لوگ دکھی ہو گئے ہیں اور وہاں کی تحصیلوں کے مسلمان لوگ بھی تڑپ رہے ہیں

[سردار بدھ سنگھ]

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کس طرح حل کیا جائے - یہ مسئلہ نہ صرف سیاسی اور اخلاقی ہے بلکہ ایک نازک اور انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے - ایک ملک و قوم کے بچے وہاں پر دوسرے ملک کی قید میں ہیں اور ان کو چھڑانے کا سوال ہے -

آپ سب لوگوں نے حال میں سنا اور پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے کچھ آدمیوں کو جنہیں چین اپنے قبضہ و قید میں رکھے ہوئے ہیں چھڑانے کے لئے امریکہ نے اس معاملہ کو لیکر جاپان، جرمنی اور سارے یورپ کے لوگوں کو ہلا دیا ہے اور ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ شائد اس مسئلہ کو لیکر دنیا میں جنگ ہو جائے گی - حالانکہ جو قید کئے گئے ہیں وہ سپاہی ہیں لیکن ہماری تو عورتیں اور بچے وہاں قید ہیں - ہماری بہت سی عورتوں اور بچوں کی عزت کا سوال ہے - اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ وہاں چلے گئے ہیں ان کی تعداد کے بارے میں کون بتائے - آج اس جگہ کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا آدمی ان آدمیوں کو دیکھنے والا نہیں ہے - ہماری سرکار کا فرض ہے کہ جو لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دریافت کرکے ان کی فہرست بنائی جائے - اسٹیٹسٹکس بنائے جائیں - آپ کے بہت سے آدمی اسٹیٹیکس بنایا کرتے ہیں ان سے یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے - ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا ہے کہ کتنے آدمی کس جگہ اور کس کیمپ میں موجود ہیں - کوئی وہاں جاکر دیکھ نہیں سکتا- ہندوستان میں جسطرح سے کیمپوں میں راشن ملتا ہے اس طرح سے ان کو بھی ملتا ہے یا نہیں یہ بھی شک ہے - نہ وہاں پر بچوں کے ہومس ہیں اور نہ کسی طرح کے سوشل ریفارمز ہی وہاں پر کئے جا رہے ہیں- آج وہاں پر کئی ہزار بے گناہ آدمیوں، معصوم بچوں اور عورتوں کی پرورش کا سوال ہے - آپ سب لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ ان سب لوگوں کو بچایا جائے - مگر آپ اس جگہ کی حالت کا مقابلہ یہاں کی حالت سے کرتے ہیں - یہ ایک اخلاقی اور انسانیت کا سوال ہے - یہ ہماری ماں بہنوں کی عصمت کا سوال ہے جو دشمنوں کے چنگلوں میں ہیں - وہ مکمل طور پر انتہائی دشمن ہیں جو ہماری ماں بہنوں اور بچوں کو قید میں رکھے ہوئے ہیں - ان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے - جن میں قتل و خون کا مادہ ہے ان سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں - اس لئے میں تہذیب اور انسانیت کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی حالت میں کوئی ملک کسی طرح سے اپنی عزت اور وقار کو قائم رکھ سکتا ہے - گورنمنٹ کو چاہیے

کہ وہ اس کام کو بڑی تیزی سے کرے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس بات کی کوشش کرے کہ ہمارے جتنے آدمی وہاں ہیں واپس لائے جائیں اور یہ دریافت کرے کہ ان کی حالت کیا ہے -

ہماری سرکار پاکستان سرکار سے کوئی بھی فیصلہ چاہے وہ ریلوے کا ہو یا پانی کا ہو یا کسی طرح کا ہو تب تک نہ کرے جبتک کہ پاکستان ہماری ان مانگوں کو پورا نہ کرے - یہ ہمارے وقار اور عزت کا سوال ہے - ہمارے بچوں اور ماں بہنوں کی عزت و ملک کی عظمت کا سوال ہے - جبتک سرکار اس طرح کا کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کریگی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا - کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جنکی وجہ سے ہم کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں - ہمارے حصے میں کوئی ایسی بات ہو جاتی جیسا کہ ملک کے بٹوارے سے ہندوستان میں ہوا تو ہمارے لوگ اپنے یہاں کی عورتوں کی عزت اور وقار کو رکھنے کے لئے لازمی طور پر ہر قربانی کرکے دنیا کو دکھا سکتے تھے - مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو جنگ ہو گئی - جنگ کی وجہ سے ہماری عورتیں بچے اور مرد سب ہی دشمنوں کے یہاں جنگی قیدی ہو گئے - وہ معصوم ہیں، کمزور ہیں، تڑپ رہے ہیں اور آپکی طرف دیکھہ رہے ہیں - آپ کو چاہیئے کہ جسطرح سے ہو سکے جس حالت میں وہ وہاں ہوں ان کو نکال کر لائیں - ہم ان کو ویلکم کریں گے ہم ان کو اپنی بہنوں اور بچوں کی طرح رکھیں گے - وہ ہمارے میں رہیں آزاد ہندوستان میں آباد ہوں اور ہمارے من کو شانتی ہو -

†[**सरदार बुध सिंह** (जम्मू और काश्मीर) : जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, यह जो बिल हाउस के सामने पेश किया गया है उसके मुतल्लिक़ १३ दिसम्बर,, १९५२ को मैं अपने खयालात मुफस्सिल तौर पर बयान कर चुका हूं और आनरेबिल मूवर, आनरेबिल सरदार स्वर्ण सिंह ने मुफ़स्सिल वजूहात बयान की हैं कि क्यों इसकी जरूरत है । अब इस पर कोई इख्तेलाफ़ राय नहीं हो सकता और न कोई दो राय ही हो सकती हैं कि आया इस काम को जारी रखना चाहिये या नहीं । मैं जम्मू और काश्मीर के नुमाइन्दे के नाते १३ दिसम्बर, सन् १९५२ की स्पीच में इसके मुतल्लिक़ बहुत कुछ कह चुका हूं । आज सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एक मामूली सवाल नहीं है और एक आरडिनरी सवाल ट्रेड का, लेन देन का, या और किसी क़िस्म के, दोनों गवर्नमेंटों के दरमियान एग्रीमेंट का नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क की उन हज़ारों औरतों, बेवाओं, बूढ़ों और जवानों की जिन्दगी और इज्ज़त का है जिनको कि जबरन ले जाया गया है । दोनों पंजाब की सूरत तो अलग है लेकिन जम्मू और काश्मीर में हजारहां की तादाद में कबायलियों के नाम पर पाकिस्तानी सिपाही और फौज के लोग बाक़ायदा तोप और बन्दूक के साथ घुस आये और हमला किया । और न सिर्फ वहां से हजारों ऐसे आदमियों और औरतों को ले गये बल्कि ऐसा खिलाफ़ इन्सानियत काम किया कि जिससे बड़ी शर्म आती है । और हमें रंज होता है

†Transliteration in Devanagri script of the above speech.

[सरदार बुध सिंह]

और हम खून के आंसू रोते हैं जब सुनते हैं कि उनको वहां थोड़े थोड़े पैसों में बेचा गया, उनकी इस्मतदरी की गई और बड़े बड़े कैम्प खोल कर उनको भेड़ बकरी की तरह रोक रखा गया। जम्मू स्टेट में मीरपुर के पास एक अलीबेग कैम्प खोला गया और उसमें हजारों की तादाद में जितने जवान थे वह सब क़तल किये गये, कई बच्चे भी क़तल किये गये और औरतों को वहां से ले गये। इस वक्त तक गवर्नमेंट ने यह तादाद दरयाफ्त नहीं की कि हमारे मुल्क के कितने लोग अब भी उनकी क़ैद में हैं। यह दूसरी बात है कि यहां काफ़ी बहस व तहक़ीकात हो रही है कि कौन और कितनी औरतें एबडक्टेड हैं और उनको कहां बसाया गया है। लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है कि हमारे कितने लोग पाकिस्तान के उन कैम्पों में बन्द हैं जो कि अपने मुल्क को आने के लिये तड़प रहे हैं। वह बेचारे देखते हैं कि हमारा मुल्क हिन्दुस्तान के साथ शामिल हो गया है और हिन्दुस्तान की बड़ी शान है, बड़ा वकार है, वहां ३५-३६ करोड़ लोग बसते हैं; उनकी इखलाक़ी, माली और हर क़िस्म की हमें मदद मिल सकती है, और फौज ताक़तवर है जिसके लिये अक्सर कहा जाता है कि अगर हमारी तरफ़ कोई आंख उठा कर देखेगा तो हम उसका पूरा मुक़ाबला करेंगे। इतनी बड़ी शानोवकार का हिन्दुस्तान और उसकी फौज और ताक़त और जनता की मदद होने के बावजूद भी इतने मासूम बच्चे और बेगुनाह मज़लूम औरतें और लोग अब तक पाकिस्तान की क़ैद में हैं, कितने रंज की बात है।

बेशक यह मुल्क महात्मा गांधी का है जहां अमन व शान्ति से काम होना चाहिये। बेशक यहां की रवायात बहुत ऊंची हैं, बहुत मुबारक हैं। यहां की तहज़ीब और एखलाक़ बुलन्द हैं। यहां की तारीख़ देखिये। एक सीता जी की क़ैद का यहां क्या नतीजा निकला? तमाम लंका खतम हो गई, तमाम हिन्दुस्तान में ग़म व गुस्सा की आग भड़क उठी उसको वापस लाने के लिये। द्रौपदी का चीर हरन हुआ, उसको बेइज्ज़त किया गया, जिस के लिये कौरवों और पांडवों में कुरुक्षेत्र के मैदान में जंग हुई और उनसे पूरा महाभारत और रामायण भरा हुआ है। लेकिन अब सूरत मुख़तलिफ़ है। तो जैसा मैं ने अर्ज़ किया, कहा जाता है कि इस मुल्क की सभ्यता, इस मुल्क की तहज़ीब, संस्कृति, इखलाक़, कल्चर, तमद्दुन बहुत ऊंचा है। और महात्मा गांधी का यह मुल्क है, महात्मा बुद्ध का मुल्क है, इसलिये लड़ाई जंग नहीं करना है। मगर इसके लिये यह भी तो निहायत ज़रूरी है कि जब तक एक भी बच्चा या एक भी औरत ऐसी है तब तक ज़बरदस्त से ज़बरदस्त कोशिश करनी है और हर मुमकिन तरीक़े से उनको वापस लाना है। अव्वल, गवर्नमेंट को इखलाक़न, क़ानूनन, हर तरह से बड़ी कोशिश करनी चाहिये कि जो उधर के ऐसे लोग यहां कहीं हैं उनको तलाश करके निकाला जाये और उनसे पूछ कर वहां अपने सम्बन्धियों के पास भेज दिया जाय और सुर्ख़रू हों। जब यह हो जायगा तो फिर एक सवाल पैदा होगा कि आया एक ग़ैरतमन्द क़ौम, ताक़तवर क़ौम, और वकार रखने वाली क़ौम का आगे क्या फ़र्ज़ है उन मासूम, मज़लूम हस्तियों को छुड़ाने के बारे में। हमारे ग़रीब मुल्क, पसमांदा मुल्क, पहाड़ के मुल्क और हिमालय के पहाड़ों के नीचे रहने वाले लोगों के मासूम बच्चों और औरतों को जबरन हमलावर ले गये हैं। उनकी बाबत भी फिकर करना है और अभी से सोचना है। उनके लिये क्या आखरी क़दम उठाया जाये? देखें कि यह क्या हो रहा है। यह क्या अमन व सुलह की बातें हैं? मैं तो कहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री ऐसी बातों से भरी हुई

है कि किसी ताक़तवर मुल्क या किसी योरोपियन मुल्क की एक औरत को कोई ले जाता है, कैद करता है या मार देता है, तो जंग शुरू हो जाती है और लाखों आदमियों का खून हो जाता है । लेकिन हम एक उसूल को बनाये हुये हैं कि जंग नहीं करना है । बेशक आप उसूल को नहीं छोड़ सकते चाहे काश्मीर रहे या न रहे, हिन्दुस्तान रहे या न रहे । वाकई उसूल व आदर्श पर कायम रहना चाहिये । यह ठीक है, हम उसको मानते हैं । लेकिन अब सवाल यह होता है कि समझौता किस से किया जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि किस के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस के साथ आप बातचीत कर रहे हैं । मैं ने कई बार कहा है कि जो शख्स बदनीयत है, बेईमान है, झूठा है, बेरहम है उसका क्या भरोसा । एक तरफ़ बेईमानी है, फरेब है, धोका है, वहशत व गन्दगी है, और एक तरफ अमन, शान्ति व सुलह का सवाल है, ईमानदारी है, तहज़ीब है, इखलाक है, और हमदर्दी से, प्यार से, मुहब्बत से, बातचीत करके मामला तै किया जाता है । ठीक है, हमारी किस्मत का क्या फैसला होता है, देखिये ।

एक हमारी बहिन ने कह दिया कि इस बिल की जरूरत ही नहीं । किसी ने उसको घुमा कर कह दिया कि इसमें यह नुक्स है । वह नुक्स है। लेकिन याद रखें कि यह इन्सानी हमदर्दी, इज्जत, ग़ैरत व वकार का सवाल है । जम्मू व काश्मीर का हिन्दुस्तान के साथ कतई इलहाक हो गया है । नेशनल कांफ्रेंस की आर्गनाइजेशन ने और काश्मीर के नुमाइन्दों ने आईनसाज एसेम्बली में इसका फ़ैसला कर दिया है । एक दफा नहीं बार बार सन् १९४८ में, ४९ में, ५० में, ५२ में, ५३ में और ५४ में—५-६ साल मुतवातिर—हम यह रेजोल्यूशन पास करते रहे हैं कि हमारा इलहाक हिन्दुस्तान के साथ हो चुका है । इस लिये जब तक सीज फायर लाइन का मसला हल नहीं होता, जब तक वह मुल्क का हिस्सा हमारा वापस नहीं आता और जब तक हमारे बच्चे, औरतें या बहिनें और मायें वहां से नहीं लाई जातीं, तब तक मैं कहूंगा कि यह सिलसिला तलाश व बरआमदगी का बराबर चलना चाहिये । जहां लाखों-करोड़ों रुपया हम फाइव इअर प्लान में खर्च कर रहे हैं तो फिर जब यहां कौम की मांओं और बहिनों का मसला है, ग़ैरत और इज्जत का मसला है, मुल्क के वकार का मसला है, वहां इसके लिये आप सोचते हैं कि कितना रुपया खर्च करें और कितना न करें । यह सारे हिन्दुस्तान की इज्जत का सवाल है । एक गरीब मुल्क एक उसूल और आदर्श को लेकर आप के साथ शामिल हुआ है । उसने अपनी किस्मत को आपके हवाले कर दिया है और अपना सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया है । लेकिन इस रंजदह मसला का हल बाकी है । मैं देखता हूं कि जब एक बिल इसके मुतल्लिक आता है तो उस पर ग़ैर मुतल्लिका तरीके पर गुफ्तगू होती है । जिनके आदमी मरे हैं, जिनके बच्चे वहां हैं, जिनकी मां-बहिनों की इस्मतदरी हुई है और जो तबाह व बरबाद हो गये हैं उन से तो पूछिये कि आया यह सिलसिला आगे चलना चाहिये या नहीं चलना चाहिये और किस हद तक चलना चाहिये । मैं बार बार यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर जंग नहीं करना है तो फिर अब आगे और क्या सौल्यूशन रह जाता है । सिर्फ बात चीत का । कहां तक मिन्नतें करते रहेंगे, कहां तक खुशामदें करते रहेंगे, कहां तक एग्रीमेंट करते रहेंगे । हम अपने प्लैज पर कायम हैं लेकिन वह कायम नहीं हैं । तो फिर क्या हमारी बहिनें वहीं रहेंगी ? क्या वह कभी आ पायेंगी भी या नहीं ? या सिर्फ हिन्दुस्तान का नकशा देखेंगी और अखबारों को पढ़ती सुनती रहेंगी ? क्या वह यहां हिन्दुस्तान के

[सरदार बुध सिंह]

वकार को, तहजीब को, उसकी ताकत को, फौज को, तोपों और बन्दूकों को और सिपाहियों को देखती रहेंगी और यह कहेंगी कि उनके लिये दुनिया में कोई मददगार और सहारा नहीं रहा ; दुनिया में कोई उनको हिफ़ाजत करने वाला नहीं है ; कोई उनको जुल्म से, तशद्दुद से और हर किस्म की ज्यादतियों से छुड़ाने वाला नहीं है ? यह कितनी दर्दनाक और खतरनाक बात है ?

हमारा काश्मीर का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ़ है । डिप्टी मिनिस्टर साहब ने पिछले दिसम्बर में कहा था कि यह सियासी मसला नहीं है ; यह इखलाकी है । मगर हमारा मसला सियासी भी है और इखलाकी भी, धर्म का भी है, सब कुछ है । अगर किसी की लड़की या किसी की औरत इगवा की जाये और उसके ऊपर दूसरे किसी शख्स की कैद के अन्दर जुल्म किया जाता है तो उसके लिये सारी पुलिस हरकत में आ जाती है और तलाश के लिये भेजी जाती है । लोग दौड़ पड़ते हैं, पुकार-पुकार कर चारों तरफ़ से आवाज उठती है हालांकि वह अपने मुल्क ही में इगवा की गई है । लेकिन हमारे यहां श्रीमती लखनपाल की तरफ़ से दलील दी जाती है कि, नहीं साहब, कोई चाहे वहां से आ सकता हो या न आ सकता हो, उन औरतों को वापस लेना मुश्किल है, गरजे कि उन को ढूंढ निकालने की कोई कोशिश न की जाये । उन पर यह मुसीबत नहीं आई, उनको यह पता नहीं है कि यह औरतें किस तरह से अपनी मुसीबत के दिन गुजार रही हैं । मैं कहता हूं कि वह कौम या वह मुल्क बड़ा व इज्जतदार नहीं है जो अपने बच्चों को, अपनी औरतों को बाइज्जत दूसरे मुल्क से छुड़ा नहीं लाता और अपने पास नहीं रखता । आप समझ सकते हैं कि हमारी तरफ़ की जो औरतें व बच्चे, जो दुश्मन के कब्जे में जबरदस्ती कैद व बन्द पड़े हुये हैं उन पर जब्र और जुल्म के साथ साथ और क्या कुछ नहीं हो रहा है । मगर हम उनके लिये खातिरख्वाह कोशिश नहीं कर सके । महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसी लड़कियों को वापस लाना चाहिये और इज्जत से बसाना चाहिये । आज महात्मा गांधी होते तो वह हर कुरबानी करके उन लड़कियों को ढूंढ निकालते और उनको गले से लगा लेते । लेकिन यह शर्म और ग़ैरत की बात है कि हम में से कई अपनी बहिनों को अपने धर्म में और अपनी कौम में ले लेने से हिचकते हैं । अपने मुल्क में तो मेम्रो क्रिश्चियन की तरह कई कौमें हैं जिन में से कई लोगों को आप शुद्ध करके अपने धर्म में दाखिल कर लेते हैं । लेकिन क्या औरतों और बच्चों के लिये तमाम दरवाजे बन्द हैं ? हम से पूछो जिनके साथ यह गुजर रही है । मेरे अपने खानदान के नजदीकी बीस औरतें आदमी मारे गये । मेरे अपने कई रिश्तेदार चले गये । मुझे अपने मुतल्लिक कुछ कहते हुये अच्छा नहीं लगता । मेरा वतन हिन्दुस्तान में शामिल हुआ है लिहाजा उसकी फारेन पालिसी में हमें पूरा इत्तिफाक है और इसी वजह से हम तमाम कुरबानी, तमाम तकलीफें और मुसीबतें व दुख बरदाश्त करने के लिये तैयार हैं । हिन्दुस्तान सलामत रहे, इसकी इज्जत बनी रहे यही हम चाहते हैं । वरना हम जानते हैं कि जैसी सूरत में हमारे अपने लोग फंसे हुये हैं उसमें तो जंग हो जानी चाहिये थी । हमारा एक एक जरर-रसीदा मर्द व औरत कहता है कि जंग हो, लड़ो या मरो, या हमारे आदमी वापस लाओ । हमने कहा कि इतने आदमी मारे गये और अगर हमने लड़ाई छेड़ी तो मुल्क बरबाद हो जायेगा, तबाह हो जायेगा । दूसरी बात यह है कि हम अपने उसूल को नहीं छोड़ सकते । हम अपने उसूल

और आदर्श पर कायम हैं और उसे हम किसी हालत में भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। अलावाअजीं हमारे दस लाख आदमी वहां रह गये हैं। सिर्फ हिन्दू या सिख भाई ही नहीं रह गये हैं बल्कि बहुत से मुसलमान भाई और बहिनें भी वहां पर रह गये हैं। एक दो की तादाद में नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में। उनके जो रिश्तेदार यहां हैं, उनकी माएं, बहिनें कहती हैं कि उनको जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया गया है, वह तड़प रही हैं। जो उनके कब्जे में हैं उनके ऊपर तशद्दुद, जुल्म व सितम ढाया जा रहा है। वहां पर कतल व खून किया जा रहा है और हमारे हिस्से के मुल्क में कई जगह मारशल ला लगा दिया गया है। वहां पर पाकिस्तान की पुलिस और फौज बाकायदा कतल व खून कर रही हैं और वहां के लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और हिन्दुस्तान की सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम को बचाओ, हमारी हालत को ठीक करो।

SHRI KISHEN CHAND (Hyderabad) : Is it all relevant to this question?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him continue.

सरदार बुध सिंह : पाकिस्तान की असेम्बलीं के अलावा वह लोग हिन्दुस्तान से कह रहे हैं कि जिस तरह से हो सकता है हमको बचाओ। उधर यह हो रहा है मगर यहां कहा जाता है कि हम ने कमिटमेंट किया है। मैं हिन्द सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त जंग हो रही थी और उसके बाद जो लड़ाई-बन्दी हुई उस वक्त क्या हमारे जवाहर-लाल जी ने काश्मीर के लोगों से यह कमिटमेंट नहीं किया था कि हम अपनी एक एक इंच जमीन वापिस लेंगे ? क्या यह वादा नहीं किया था कि जब सब कुछ ठीक हो जायेगा, रेडर को भगा दिया जायेगा, तो हम अपनी सारी जमीन को वापस ले लेंगे ? आज हमारी रियासत में चार मील से दो सौ मील तक वह लोग घुस कर अपना कब्जा जमाये हुये हैं और हमारे जो आदमी वहां पर है उनके ऊपर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है। आप सब लोग अखबारों में पढ़ते ही होंगे कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर के लोग दुखी हो गये हैं और वहां की तहसीलों के मुसलमान लोग भी तड़प रहे हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि यह मसला किस तरह हल किया जाये। यह मसला न सिर्फ सियासी और इखलाकी है बल्कि एक नाजुक और इन्सानी हमदर्दी का मसला है। एक मुल्क व कौम के बच्चे वहां पर दूसरे मुल्क की कैद में हैं, उन को छुड़ाने का सवाल है।

आप सब लोगों ने हाल में सुना और पढ़ा होगा कि अमरीका के कुछ आदमियों को जिन्हें चीन ने अपने कब्जा व कैद में रखा हुआ है, छुड़ाने के लिये अमरीका ने इस मामले को लेकर जापान, जर्मनी और सारे यूरोप के लोगों को हिला दिया है और ऐसा मालूम होने लगा था कि शायद इस मसले को लेकर दुनिया में जंग हो जायेगी। हालांकि जो कैद किये गये हैं वे सिपाही हैं लेकिन हमारी तो औरतें और बच्चे वहां कैद हैं। हमारी बहुत सी औरतों और बच्चों की इज्जत का सवाल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे जो लोग वहां चले गये हैं, उनकी तादाद के बारे में कौन बताये ? आज उस जगह की हालत यह है कि कोई भी हमारा आदमी उन आदमियों को देखने वाला नहीं है। हमारी सरकार का फ़र्ज है कि जो लोग वहां पड़े हुये हैं उनके बारे में दरियाफ्त करके उनकी फेहरिस्त बनाई जाये, स्टेटिस्टिक्स बनाये जाये। आप के बहुत से आदमी स्टेटिस्टिक्स बनाया करते हैं, उनसे यह काम आसानी से हो सकता है। अभी तक यह पता

[सरदार बुध सिंह]

नहीं लगा है कि कितने आदमी किस जगह और किस कैम्प में मौजूद हैं। कोई वहां जा कर देख नहीं सकता। हिन्दुस्तान में जिस तरह से कैम्पों में राशन मिलता है उसी तरह उनको भी मिलता है या नहीं, यह भी शक है। न वहां पर बच्चों के होम्स हैं और न किसी तरह के सोशल रिफार्म्ज ही वहां पर किये जा रहे हैं। आज वहां पर कई हजार बेगुनाह आदमियों, मासूम बच्चों और औरतों की परवरिश का सवाल है। आप सब लोगों की ख्वाहिश यही है कि उन सब लोगों को बचाया जाये। मगर आप उस जगह की हालत का मुकाबिला यहां की हालत से कैसे करते हैं? यह एक इखलाकी और इन्सानियत का सवाल है। यह हमारी मां-बहिनों की इस्मत का सवाल है जो दुश्मनों के चंगुलों में हैं। वह मुकम्मल तौर पर इन्तहाई दुश्मन हैं जो हमारी मां-बहिनों और बच्चों को कैद में रखे हुये हैं। उनमें इन्सानियत खत्म हो चुकी है। जिन में कतल व खून का माद्दा है उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिये मैं तहजीब और इन्सानियत के नाते यह कहना चाहता हूं कि ऐसी हालत में कोई मुल्क किस तरह से अपनी इज्जत और वकार को कायम रख सकता है। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इस काम को बड़ी तेजी से करे और जहां तक मुमकिन हो सके इस बात की कोशिश करे कि हमारे जितने आदमी वहां हैं, वापस लाये जायें और यह दरयाफ्त करे कि उनकी क्या हालत है?

हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार से कोई भी फैसला, चाहे वह रेलवे का हो या पानी का हो या किसी तरह का हो, तब तक न करे जब तक कि पाकिस्तान हमारी इन मांगों को पूरा न करे। यह हमारे वकार व इज्जत का सवाल है। हमारे बच्चों और मां-बहिनों की इज्जत का व मुल्क की अज़मत का सवाल है। जब तक सरकार इस तरह का कोई सख्त रवैया अख्तियार नहीं करेगी तब तक यह मसला हल नहीं होगा। कई ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह से हम कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। हमारे हिस्से में कोई ऐसी बात हो जाती है जैसा कि मुल्क के बटवारे से हिन्दुस्तान में हुआ, तो हमारे लोग अपने यहां की औरतों को इज्जत और वकार को रखने के लिये लाजमी तौर पर हर कुरबानी करके दुनिया को दिखा सकते थे। मगर बदकिस्मती से हमारे यहां तो जंग हो गई। जंग की वजह से हमारी औरतें, बच्चे और मर्द सब ही दुश्मनों के यहां जंगी कैदी हो गये। वह मासूम हैं, कमज़ोर हैं, तड़प रहे हैं, और आप की तरफ़ देख रहे हैं। आप को चाहिये कि जिस तरह से हो सके जिस हालत में वह वहां हों उनको निकाल कर लायें। हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनको अपनी बहिनों और बच्चों की तरह रखेंगे। वह हमारे में रहें, आज़ाद हिन्दुस्तान में आबाद हों और हमारे मन को शान्ति हो।

श्री कन्हैयालाल दौ० वैद्य (मध्य भारत): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। माननीय सरदार बुध सिंह जी के जोशीले भाषण के बाद में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले इस सदन की दो बहनों ने भी इस बिल पर काफी प्रकाश डाला है और कल तो उनमें कुछ आपसी वाद-विवाद सा खड़ा हो गया था।

जहां तक कि इस बिल का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि हमें किसी उत्तेजना के वातावरण में इस सारे प्रश्न के ऊपर सोचना है; शांति के साथ हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि किन हालात में इसे यहां लाया गया। जिन घटनाओं की चर्चा सरदार जी ने यहां की उससे प्रतीत होता

है कि उनको वास्तव में उनका बड़ा दुख है । संसार का इतिहास लिखने वाले लोग ऐसी घटनाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण उल्लेख करेंगे कि किन अत्याचारों से और किस प्रकार की बर्बरता से इस देश में एक बड़ा महाकांड हुआ ।

जहां तक हमारी माताओं और बहनों का प्रश्न है, जैसा कि श्रीमती चन्द्रावती जी ने कल कहा था, उनके सम्बन्ध में हमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और उसके लिये सामाजिक विचारों में क्रान्तिपूर्ण परिवर्तन करने के लिये इस देश में और पाकिस्तान में प्रयत्न करना चाहिये । यह प्रयत्न जब तक नहीं होता है, यह कोशिश जब तक नहीं होती है, तब तक इस सवाल का हल ठीक ढंग से नहीं हो सकता । माननीय मंत्री महोदय ने कल जो आंकड़े दिये थे उन आंकड़ों से यह ज़ाहिर हुआ है कि बहुत सी स्त्रियों और बहुत से बच्चों ने जो पाकिस्तान में थे उन्होंने इस देश में आने से इन्कार कर दिया और बहुत सी स्त्रियों और बहुत से बच्चों ने जो हिन्दुस्तान में हैं उन्होंने यहां से जाने से इन्कार कर दिया । बहिन निगम ने यह कहा कि यह क्या सम्भव है कि वे इस प्रकार से उन आततायियों के पास रह सकती हैं ? लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े माननीय मंत्री महोदय ने दिये, उनसे पता चलता है कि दोनों राज्यों की सरकारों ने इस बात की कोशिश की कि वे लोग अपने-अपने देशों को वापस लाये जायें । लेकिन जैसा कि श्रीमती चन्द्रावती जी ने कहा, अभी सामाजिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि उसमें वे स्त्रियां अपने समाज में जाने के लिये तैयार हों, उन घरों में जाने के लिये तैयार हों और इज्ज़त के साथ वे वहां रह सकें और इनके कारण सरकार के इतना प्रयत्न करने पर भी उसको वह कामयाबी नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिये थी । सरकार को दोष देना या सरकार के प्रयत्नों में खामियां निकालना तो आसान है, लेकिन वास्तव में यह प्रश्न इतना जटिल है कि इसकी तह में हम जितना जायें उतनी ही बातें हमें मालूम होंगी । एक स्त्री को दूसरे परिवार में से पता लगा कर निकाल लाना कोई आसान काम नहीं है । मैं बहुत से राज्यों के ऐसे कई क़िस्से जानता हूं और मेरी जानकारी में भी है कि अभी तक ऐसी कई स्त्रियां ऐसे कई परिवारों में कई स्थानों में मौजूद हैं, किन्तु उनका पता लगाना, उनको ढूंढ निकालना, ये जो शासनकर्ता लोग हैं उनके लिये भी एक कठिनाई का प्रश्न बना हुआ है । इसलिये मानवीय प्रश्न के दृष्टिकोण से सरकार जहां यह प्रयत्न कर रही है वहां सामाजिक काम करने वाली जो संस्थायें हैं या लोग हैं उनका भी यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह सरकार के साथ सहयोग करें और जैसा कि बहिन निगम ने कहा, सरकार अमुक संस्थाओं और उनके कार्यकर्ताओं को अपने प्रयत्नों में सम्मिलित करे, तो उसके लिये मैं नहीं समझता कि सरकार उन प्रयत्नों में कोई कसर रखती है और किसी प्रकार से ऐसे जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, जो उपयुक्त व्यक्ति हैं, उनको वह अपने कार्य में शरीक़ नहीं करती होगी ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may continue your speech after lunch. The House stands adjourned till 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at half-past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री कन्हैयालाल दौ० वैद्य : उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुधार के कामों में समाज सुधार करने वालों का सहयोग लिया जाय, यह सुझाव भी इस सदन में रखा गया है । यदि प्रारम्भ से इस विभाग का इतिहास

[श्री कन्हैयालाल दौ० वैद्य]

देखा जाय तो यह कहना आवश्यक हो जाता है कि सरकार ने यह सारा कार्य समाज सुधार करने वाले जो लोग थे उन्हीं के हाथों में देकर उनके पूरे सहयोग से इस प्रश्न को निपटाने की चेष्टा की है । मैं इस सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश की एक प्रमुख कार्यकर्त्री, मृदुला साराभाई जैसी महिला इस विभाग की इंचार्ज रही हैं और उन्होंने सदैव इस बात की चेष्टा की है कि जितने भी सम्भव उपाय हो सकते हों, उन उपायों से ऐसी अपहृत माताओं और बहिनों को निकालने का प्रयत्न किया जाय । राम सीता और महाभारत के युग की कथायें भी यहां सुनाई गई । यह ठीक बात है कि एक स्वतन्त्र देश के नागरिक के नाते प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है । जो सम्बन्ध हमारे देश के और पाकिस्तान के हैं उनको देखते हुये मैं समझता हूं कि संसार का कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि हिन्दुस्तान की सरकार, जो अन्यायपूर्ण नीति कोई सरकार या राष्ट्र इस देश के साथ चलाना चाहता है, उसका प्रतिकार या उसका समुचित उत्तर देने के लिये तैयार नहीं है । यह सारे संसार ने देखा कि किस प्रकार कुछ राष्ट्रों ने पाकिस्तान को फौजी और दूसरे प्रकार की सहायता देकर एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, किन्तु हमारे राष्ट्र के नेता जवाहरलाल जी ने उस सारी नीति का भंडाफोड़ कर दिया, उस नीति का पर्दा फाश कर दिया और उसके परिणामस्वरूप आप देखते हैं कि केवल एशिया में ही नहीं बल्कि सारे संसार में शान्ति के वातावरण में बहुत योग मिला । हम एक सेक्युलर राष्ट्र की राजनीति को लेकर चल रहे हैं और हम हिन्दू मुसलमानों के दृष्टिकोण की राजनीति को ले कर नहीं चल रहे हैं । इसलिये यदि हम पुरानी कहानी को दोहराने के लिये खड़े हों तो मैं समझता हूं कि हमारी बहुत सी बातें पीछे रह जायेंगी । साम्प्रदायिक मनोवृत्ति की बातों को उखाड़ करके मैं नहीं समझता कि देश का कल्याण हो सकता है । संसार में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हमारा राष्ट्र उच्चादर्शों को लेकर और सेक्युलर नीति को ले कर चल रहा है और उसका हमें समर्थन करना चाहिये । इसी नीति का पालन करते हुये हमें ऐसी अपहृत बहनों और माताओं की समस्या को हल करना चाहिये ताकि उनकी इज्जत से समाज में रहने की व्यवस्था हो सके । माननीय मंत्री ने जो आंकड़े बताये हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी अपहृत महिलाओं को निकालने की चेष्टा की गई है और उनको पूरा मौक़ा दिया गया है, किन्तु बहुत सी महिलाओं ने यह समझा कि जिन परिवारों से वे आयी थीं उनमें उनका रहना सम्भव नहीं होगा, इसलिये विवश हो कर उनको वापस जाने की स्वीकृति देनी पड़ी । सरकार इससे अधिक क्या कर सकती थी ? यदि सामाजिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से कुछ स्त्रियां जिस घर से वे गई थीं, उस घर में वापस नहीं आ सकतीं, तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी स्त्रियों के लिये ऐसे काम काज और व्यवसाय स्थापित करे जिससे वे एक सम्मानपूर्ण ढंग से रह कर अपना उदर पोषण कर सकें । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी । मान लीजिये, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं या जो पाकिस्तान से यहां आना चाहते हैं, लेकिन वे सामाजिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिये हर प्रकार की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है ।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि अब यह विधेयक अनावश्यक हो गया है । सरकार

न इस सम्बन्ध में एक कमीशन नियुक्त करने का निर्णय किया है। यह कमीशन सब पहलुओं पर विचार करेगा और यदि उस कमीशन का यह सुझाव हुआ कि अब यह कार्य अनावश्यक है तो मैं समझता हूं कि सरकार को उसे मानने में कोई झिझक नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI H. C. MATHUR (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, I feel very grateful to the hon. Minister for the informative speech that he delivered and for the facts and figures which he doled out to the House. This saved a lot of criticism. There was a general feeling about the working of this organisation and that feeling was so adverse that during the debate on the last occasion we indulged in all sorts of accusations. Even this year, in the other House, Members, while speaking on this Bill, had come out with all sorts of criticisms. The information which has been given to us proves two facts very clearly: one is that the organisation has functioned in an impartial manner; and the second is that the organisation has been able to create an atmosphere in the camps where the women, who have been taken there, could take an unbiased decision in a free atmosphere. We find from the facts placed at our disposal that about 50 per cent, of the women had opted to stay in India and similar is the case on the other side We also find that almost every case that had gone to the court had failed which is further proof that the screening in these camps has been very fair. I very much wish that informative literature, a sort of periodical literature, could be submitted to Parliament much ahead of such Bills being discussed in the House. It would be better if we had a sort of six-monthly report because now we are taking the facts as given out by the hon. Minister at their face value. Of course, we have no reason to doubt them, but il will have to be conceded that we had no-time to have a real appreciation of-the facts, that we had no time to discuss these facts and that we had no time to ask for further information. If we have such periodical reports, it will serve a double purpose; it will keep the Government vigilant about it—it will keep the Government alive to circumstances—and it will place at our disposal facts and figures on the basis of which we could make further enquiries, proper studies and have a proper appreciation of the circumstances. Taking the facts as there, have been given out by the hon. Minister, I have no hesitation in saying that, so far as the organisation on this side of the country is concerned, it has functioned remarkably well. Sir, these very facts tell certain stories. These very facts lead us to certain conclusions and they lead us to think of some very vital and delicate problems.

In this connection, I wish to invite the attention of the hon. Minister to what had been said last time by the hon. the Prime Minister. There is a sharply divided opinion in this matter as was typically demonstrated by the two lady speakers. Even when we were discussing it last time and when we are discussing it this time the same[s] arguments were and have been developed and there is in this House a very large section of people, as Professor Wadia very correctly pointed out, who are of the same opinion as the lady speaker who spoke first who said that there should be some finality about it. Again, there are many people who feel the other way round. But taking into consideration all these facts, taking into consideration both the viewpoints, last time when there was a very strong criticism, the hon. the Prime Minister who, I believe, is really in charge of this organisation- and work, because I understand that this organisation is working under the External Affairs Ministry— it is by some arrangement that the

[Shri H. C. Mathur.] hon. Minister who is at present conducting the Bill is in charge of it-said this: "Obviously this way of dealing with the problem cannot be continued indefinitely". It was in relation to the same two views which had been very strongly put forward and he himself felt that— he is a very sentimental person; he is one who always advocated that—if there was even one woman left in this country we should feel morally bound 10 come out and see that if she was being detained against her will, she should have been recovered and restored to proper quarters. But even he, Sir, in the light of the facts, in the light of the criticism offered very strongly by the House, had to make these observations: "Obviously this way of dealing with the problem cannot be continued indefinitely. ***But taking everything into consideration we do feel strongly that we should carry on for another year or so." That is all. "Of course, we have asked for extension by another quarter, because extension by a year comes at an awkward time, in the middle of the Budget Session, and the House would be inconvenienced. Practically it is for a year, and we shall, in this period, in a sense, revise our method of approach, where it is considered necessary, and try, if possible, to finalise the problem."

Now, Sir, he was very apologetic and the hon. the Prime Minister had even to ask for an extension for more than a year last time and as he has mentioned, it was not one year; it was a year and a quarter and he had to give an explanation to thfi House as to why he was asking for a longer time because if it was just one year, that period would terminate when we would be discussing the Budgets and it would not be convenient for Parliament at that time to take up this question. In view of this particular fact he felt it and he just pleaded to let the period be extended to a year and a quarter, which is up to May 1955. and he gave a sort of an understanding that during this period they would be able to have some new approach to this problem, that they would be able to finally decide this matter, and, Sir, it was thought that the cases which were pending before the Government would be decided during that period.

The hon. Minister, while piloting this Bill and while delivering his long speech with all the information has not mentioned a word about what the hon. the Prime Minister had said last time whether they stand by the same commitments or assurances which the hon. the Prime Minister gave in this connection, or not. It is my feeling that the Government has not at all been able to tackle this problem in a vigorous manner as could be expected of it. At least they failed in bringing pressure on the Government on the other side or in evolving an organisation or method by which the legitimate demand under this Act could be fulfilled. For the first time, Sir, when in 1949 an extension was asked for, it was stated by the late Shri Gopala-sw; ni Iyengar that they were anxious to see that about the 2,000 of the unfortunate Indian girls who were in the hands of the Pakistani officials something was done. I would like the hon. Minister to throw some light on it, what they have been able to do about it, whether they have been able to take any effective steps in that direction, what has happened to these 2,000 unfortunate victims who are not being recovered from there, whether any search has got to be made for them but against whom the allegations are that they are in the hands of the Pakistani officials. We have not h°ard about it. It was in 1949 tha. we were given the assurance that all efforts would be made in that, direction. But I find, Sir, not a word about it. We certainly would like to be enlightened on this matter. If during these seven years it has not been possible for the

hon. Minister to take any effective measures in respect of these women about whom this Parliament and he or his predecessors have been talking, then it is better for him to confess his inability and impotence in the matter and give it up, or he should give us a written assurance that he has these effective measures in his mind and he is going to proceed in this manner in this matter. Sir, the hon. Minister has made his case so innocent as that. He makes out that the best they could do was to appoint a fact-finding committee; these are matters which are being dealt with internationally, matters which are being dealt with at the Governmental level; we cannot very much help matters; we have got to come to a certain understanding with a foreign Government; it takes time and the Fact Finding Commission itself could not be appointed for such a long. time. And now he says that, so far as he was concerned, he had only asked for time up to the end of November so that the report of the Fact Finding Commission may be in his hands. It looks all very nice and very fine. But, Sir, may I ask him: when the hon. Prime Minister gave that undertaking or gave that sort of understanding in the other House, was it not in his knowledge that tbey were dealing with another Government, that they were dealing with a Government of whom he has had a sad experience for the last seven years? I think it was in full consciousness of the task that lay before him that he gave a sort of understanding to the other House that within a year they will be able to clear all these cases and finally decide this matter. He hoped to decide this matter earlier than May 1955. Today we are in the month of September and a period of three months' grace has bee'.i given and yet we do not see anything accomplished in this matter. So, v/e lose confidence in the Government naturally because of the extremely poor performance of the Government in this particular matter. It is not in a spirit of bar-

gaining that we speak. I am in perfect agreement with my hon. friend. We are not dealing with rupees, annas and pies; we are not dealing with certain dead material. We cannot deal with this matter in a business-like manner. I entirely agree with him.. I would go even a step further. I do not consider this to be a Hindu-Muslim question; I do not even consider this as a political question. I am in perfect agreement with him that it is a human question. That is all right. But have they been able to tackle this question in a human manner? Have they been able to fulfil and satisfy the legitimate aspirations and demands of the people of this country? That is my question. They have not been able to answer this all these seven years but they have been coming before Parliament year after year and asking for time. For what? Again, there are no reasons given. We do not stand convinced tnat anything is likely to come out of the weak hands of this Government. And if it is so, Sir, we will have to think twice before we extend the time. My hon. sister here wanted the timftto be extended by two years and she advanced reasons for it. I do not at all subscribe to that view particularly because of the much-awaited report of the Fact Finding Commission.

Now, taking into consideration the figures which have been placed in our hands, it is of course a sort of solace and consolation to us thrft of the 2,000 abducted persons taken into the camp more than a thousand opted to stay here. Now, ±et us examine what happens. These thousand women had to be taken away from their homes and brought over to these camps. You may not have destroyed the peace and harmony of that house but certainly you have destroyed the peace and harmony of that woman. And the evil effect that is likely to be there on the children has got to be taken into consideration. The innocent child does not knov

[Shri H. C. Mathur.] anything about the old incident. One fine morning he finds that his mother is being taken to the camp. She stays there and the child is re noved from her. It has a very big psychological effect on the children wnich cannot be denied. We further find a large number of children being kept here and the main criterion which my hon. friend has stated is the choice of the woman— whether she wants to stay here or whether she wants to go there. And while discussing this problem my hon. friend said, "Naturally, the interest of the children is also taken into consideration". I would like the hon. Minister to throw some light on this subject as to how he reconciles the two, how he thinks that the sending away of the woman from here to the other country reconciles with the interest of the majority of children who are left here without mothers. What is the criterion? If the Government comes to a decision that it is in the best interests of the children that the mother should stay here, may I know whether the Government has got the power to ask the mother to stay on here? In such cases what is the jurisdiction which the hon. Minister exercises? What is the power which he exercises? And what is the criterion which is followed? I cannot see how the hon. Minister thinks that it is in the best interests of the children that their mothers should have been sent to the other side. How has it served the interests of the vast majority of children who have been left behind? I feel that it is not so much the choice of the woman that should prevail. Children, in this consideration, are very important.

I feel, Sir, that you are in a hurry and I will not touch upon the other points which have already been covered by my hon. friends. If I find an occasion at the third reading stage, I shall further say a few words.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kishen Chand, we are to close this debate at 3.15 and the hon. Minister wants half an hour for his reply.

SHRI KISHEN CHAND: Sir, I do not want more than ten minutes.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I gave my name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not there.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is there, Sir, that I should speak on the 31st.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you very anxious to speak? Because I have not got your name.

SHRI BHUPESH GUPTA: Yes, Sir. I thought my name was included. I gave it yesterday and Dr. Subbarayan was in the Chair at that time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How much time do you propose to take?

SHRI BHUPESH GUPTA: About 10 minutes; rather 15 minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not more than 10 minutes.

SHRI BHUPESH GUPTA: In that case I do not think that I should speak on this subject. Let our voice be not heard.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I do not want to shut you out. You can take 10 minutes. Mr. Kishen Chand.

SHRI KISHEN CHAND: Sir, the hon. Minister when he moved this Bill expressed a very correct sentiment when he said that this problem was a humanitarian problem. It is a problem of women who are being kept in either country against their will and we should help their transfer if they so desire. In so far as the hon. Minister has expressed this sentiment I am in full accord with him but in spite of that I cannot lend my support to this Bill. I agree with him that if there are unfortunate

cases of women in either country who want to come back to their original homes, we should help their return but the methods that are being adopted of breaking up homes are not very fair. After all, there is a time-limit to everything. You know, Sir, in ordinary human life, if there is a bereavement, the bereaved person feels that the friends who are making enquiries are really reminding him of the serious loss. Similarly, in this case, seven or eight years ago, certain women were left behind in Pakistan and some were left in India against their will. They have settled down with certain other persons, borne children and are living there. Now, what happens after seven or eight years? The officers of Recovery Department go to homes, enquire about these women and they are transferred to camps. There, all sorts of social workers and relatives come from Pakistan and for days, harassment of these women goes on. It really amounts to harassment. Temptations are offered that "If you go back to Pakistan; you will be so well treated; you will be almost a national hero." And, in spite of these temptation, a large number of women do not want to go back. Is it right that we should interfere in a happy home? It has become a happy home after living for seven or eight years.

Well, the hon. Minister gave figures of persons, of women, who have been sent to Pakistan as 20,623. Well, the hon. Minister was not prepared to make any conjecture about the total number of women who were abducted in India. I suppose even a very optimistic estimate will not place it much beyond 23 or 24 thousand. Out of that number, 20,600 have already gone. So, even on a very liberal estimate, about two or three thousand women all told are left behind in India. Out of those, two thousand have refused to go back. That means that there are hardly a few hundred women now left and for the sake of those few hundred women, we keep an organisation which interferes and meddles into every home, and tries to disrupt it as far as possible. In our marriage laws, for the sake of children, we have made divorce very difficult, while here, against their will, these women are sent to Pakistan, breaking up their homes, separating them from their children. Is it right?

On the other side, the estimate of women—Indian women—left in Pakistan would be about fifty thousand. Out of that figure, only nine thousand have come to India and now, the present rate of recovery during the last two months is very low. The hon. Minister said that all told, 79 persons were put in camp of whom 49 came to India. So, now it has come to 10 or 15 per month. Is it worthwhile for the sake of 10 or 15 to keep this festering sore alive between the two neighbouring countries?

An hon. Member spoke very eloquently about our epic poems and said that in the glorious past, great wars were fought for the sake of one woman. Sir, our conception has completely changed and now women are not considered as chattels and wars are not fought for one or two or even hundreds of women. They are fought for certain moral principles or economic principles. So, to cloud the issue with certain sentiments is not fair. I will give you an example. A few aviation officers of America are detained in China. America does not go to war with China because a few persons are detained in China. Similarly, if a few persons of Indian origin are detained, we should use diplomatic methods or political methods for their recovery. But, to suggest as was done by certain hon. Members—not by the hon. Minister— that we should go to war because certain women of Kashmir are now in Pakistan-held territory is most unfair and it is not right to rouse passions in that way. Several hon. lady Members also tried to look at

[Shri Kishen Chand.] it from an emotional point of view. I think there is no question of emotion. Well, it was a very sad and very sorry thing that abduction took place and the women against their will were held in the other territory. During the last seven or eight \ ears, the Government has done really good work and I congratulate the hon. Minister and the Department which has carried on the work.

My opposition to this is not because the Department is not carrying on good work. There is a limit to everything, even to a good thing. We have been maintaining this policy for the last seven or eight years and now the recovery work has more or less come to a standstill. It has become such a nominal figure that it is not worthwhile in the international interest, in the interests of good neighbourliness of two countries, to keep on this Department.

In the end, in spite of agreeing with the hon. Minister in his approach to this problem, I would humbly submit to him that he should reconsider this question and should not continue this Department for any longer than a few months more.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Deputy Chairman, I thought that it would be possible to get a little more time for me to speak on this subject, which is by no means controversial. Yet, it is just possible, within the short time available, that I may put certain suggestions for the consideration of the Government. Unfortunately, you do not have my slip with you.

There is no doubt in my mind that Government is sincere in the matter and I certainly appreciate the objective manner in which the hon. Minister piloting this Bill has presented the proposition to the House. He has presented it with sympathy. I only hope that that sympathy would be balanced by speed and the right type of action.

It is unfortunate, Sir, that some hon. Members spoke, trying to rouse passions. I do not deny that such matters give room for passions. If they wish they can rouse passions; there can be no doubt about it. But I think that, if we have learnt anything from our bitter experience, it is this that the problems outstanding between the two countries and between communities could not be solved—will never be solved—by rousing the passions, elemental sentiments or emotions of people. It is necessary, in this connection, to view the whole thing from a broader angle—to take what it is and not imagine what it should be, and then on the basis of an objective appraisal of the situation, proceed to tackle the problem. It is a good thing that the Government has tried to tackle this problem. After all, if there is any woman in this country or in that country who is kept against her will with any person, efforts should be made to recover her. If Pakistan does not do so, it does not explain why we should not do so. It is a humanitarian problem. It is a problem which relates to certain fundamental tenets of our civilized life. It is not a question which deals with trade between the two countries *so* that when one party does not fulfil his obligation, the other party is under no obligation *to* discharge his own part of the contract. This matter we do not view that way. Well, I think the hon. Minister was quite right in his approach to this matter. Now, as far as Pakistan is concerned, I am not in a position to speak because the material that is necessary to speak on their activities is not before us, except whatever little facts have been given. I do not blame or commend, because it is not possible for them to produce everything for the Pakistan Government.

But on the basis of what we have got from the Government here, it appears that the problem is still of some dimensions. Undoubtedly, a problem of this sort is delicate, com-

plicated and is not easy of solution. j At the same time, we all feel that j we should proceed with this question and look forward to the day when this chapter, like many other melancholy chapters we got from the partition of the country, would be closed.

Here, I think I can join issue with the Government in regard to certain matters. The debate took place last year in February and I appreciate the manner in which the Government hr.j treated certain portions of the debate. After all, the Government met in conference with the representatives of the Pakistan Government in the month of May, within two months of the debate, and came to an agreement. Whatever one might or might not say about this agreement, it was the right approach for this Government. The representatives of this Government and those of Pakistan sat across the table to decide certain things and find out a common solution. I think problems between the two countries will have to be tackled in this manner. As far as we are concerned, we know where we stand *vis-a-vis* this Government or the Pakistan Government. It is well-known to you. But at the same time I am quite clear in my mind that the Government-level discussions would be called for time and again. Even if that failed, we should not go on rousing passion, but we should try again to sit across the table, to summon them, to appeal to them to sit round a conference table and discuss such problems, so that such problems may be solved in that manner. People naturally co-operate with all good and sincere endeavour to solve such problems. Therefore, the Government did a very right thing in holding the conference and coming to an agreement. But my complaint against the present Government is this, that the agreement has not been acted upon in the proper way. As you know, a long time has been taken for the appointment of the Fact Finding Commission which according to the agreement—a copy of which I have got with me— should have been appointed immediately after the conference was held and the report of that Commission should have been available within six months. Now, more than a year has passed. We have not got this report and from the statements that have been made by the hon. Minister we find that the Commission itself came to be appointed about a year after the conference took the decision. This seems to me to be an inordinate delay in this matter where we must have speed. Otherwise, the agony will be prolonged, the bitterness will be continued. This problem must be tackled speedily. Speed is the essence of the problem because we want to close that chapter—a chapter of sorrow and tears, agony and suffering. If we view it from that angle, this time should not have been lost. I quite understand that when an agreement of this sort is arrived at between two Governments, some of the things depend on how the other party is acting. But I would require an explanation from the Government, for enlightenment, as to what came in the way of it functioning in this matter with a little more speed than it has shown.

Then, the Fact Finding Commission, again, is not a very satisfactory one. I find that a pensioned officer has been appointed as one of the members of the Fact Finding Commission. His name is there in the statement that I have got. Now, why a pensioned officer? Is he particularly qualified in the social field so that you must have him? Did he acquire certain special experience during his service, so that he should be placed in that position? I do not find a proper answer to these, because the Minister has not thrown any light on that matter, although this kind of appointment has been called in question in the debates in the other House. I should have thought that when you appoint such persons on a Commission of this sort you should have

[Shri Bhupesh Gupta.] proper people, from among those who have got some experience in social work and all that. And then you can invest that person with proper authority, if necessary, by passing a law. Now, Sir, here the Fact Find ing Commission looks to me too much of a bureaucratic institution and the hon. Minister should have reasoned about this thing. It is a human ques tion, not an administrative or politi cal question; so that persons with experience of social service, flowing with human kindness and sympathy would be able to tackle the job expeditiously and well. I think the hon. Minister was not fully alive to this aspect of the matter. I am not talking about the official whom the Pakistan Government have put cm the Board. That is not my business here. I suppose they have followed more or less in the same footsteps.....................

THE MINISTER FOR WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SARDAR SWARAN SINGH) : Maybe that we have followed them!

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore, the trouble is there. Such a Commission—a retired Commission—will function in a retired way. We want a Commission full of life, sympathy, vision, understanding, courage and initiative. Such a Commission should be appointed that will go into the problem and leave no stone unturned until and unless a solution is found. But if you put a retired official there it will move as if it is a ramshackle vehicle with all the breakdowns, with all the Interruptions and all that. Stream-lined committees should be appointed in such matters just as you have in other fields when you tackle problems of such dimensions. Therefore, I appeal to the Government to consider whether it has done the right thing. Now, this task is over. If similar commissions have to be appointed in future in order to ascertain the dimensions of the problem and its implications, I think a Fact Finding Commission of a different sort should be appointed.

Then, I find that according to the agreement the High Power Officers should have met at least five to seven times; but they met about two to three times only. Perhaps, because the Commission came to be appointed later; it does not speak well of the way this machinery has functioned any way. Therefore, that is another point.

I want to say something about the Tribunal. I find there are three names given here:—

1. Pandit Thakar Das (India)
2. Mr. I. H. Jafri (Pakistan)
3. Shrimati Bhag Mehta, Adviser

Suddenly I find an adviser. Why is she not given full powers? Why should she bq an adviser? I do not know. I assume that she is a ladv who has got experience in social work, but in that case why should she be put as an adviser? She should be given proper powers. About the other gentleman representing Pakistan we cannot speak. But if we can offer our friendly suggestions, the other two gentlemen on the Tribunal shoula also be replaced by people with some kind of experience in social work, people who know how to tackle such problems, people who have a humane approach to the problem. People who know how to talk to these unfortunate women and people, who can sympathetically tackle this problem. Police officers are not the right kind of persons. Why must you go in for police officers oven in such cases? j do not deny that for recovery purposes you must require their assistance now and then, but they need not constitute the Tribunal. The Tribunal should be constituted of people of a different mould. That is what I am saying.

Now, Sir, lastly my point is this. The administration of this Department has been called in question in the other House and in this House also I was reading the Prime Minister's speech. He wanted the problem to be solved humanly and as rapidly as possible. That is what he said on the 25th of February last year when he intervened in the debate and spoke on this Bill. If you have a bureau-

cratic machinery for solving this problem humanly and rapidly, it will neither be solved humanly nor will it be solved rapidly. That has been the common experience not only of our benches, but of the benches there also. I think, the hon. Minister knows in his heart of hearts that bureaucracy moves slowly. It takes a lot of lime to decide things. It suffers from a certain disease called wooden-head-edness. *(Time bell rings.)* I am finishing, Sir. Therefore, my suggestion would be that the whole administration in respect of this problem should be entrusted to a properly-constituted social organisation, and especially women should be brought in and given responsibilities, and the bureaucratic machinery should be eliminated. So far as the administrative machinery is concerned, tneir help would undoubtedly be required, but I think otherwise the whole thing should be left in the hands of social workers, no matter from which part you draw them. They should be in charge of this great responsibility and this sacred responsibility. I think, if youi place them in charge of this responsibility, the machine will move faster and with sympathy, and it will be possible for us to settle this question and solve the problem both humanely and rapidly.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I am extremely grateful to the hon. Members belonging to the various parties in this august House for the very anxious thought that they have given to this very complicated problem. The fact that there is some difference of opinion as to what should be the best way of tackling the problem is quite understandable. In a problem so complex, so difficult and so delicate, it is quite natural that there should be such a difference of opinion.

Sir, functioning of the human mind is so mysterious,' and results flowing therefrom are so different in different circumstances that by the same process of reasoning and ratiocination it is quite possible to arrive at conclusions which may not be quite identical. I am, however, extremely grateful to the hon. Members who have thrown light on different aspects of this problem.

As a result of the observations made by the hon. Members on the last occasion in this House as well as in the other House, Government reviewed the whole position, had consultations with the Government 01 Pakistan, and settled some of the controversial matters, and arrived at certain unanimous agreements. I am happy to note, Sir, that by and large, there has been appreciation of the agreements that were thus arrived at. So far as the main question is concerned, there is absolutely no difference of opinion about the approach that has to be brought about for the solution of this problem. All sections of this hon. House agree that this problem should be treated as a human problem, free from any political controversy, and we should not look at it with anv rancour or With anv Spirit either of parity or of retaliation. That is a very happy state of affairs, because if all of us agree upon the approach, then it is easier to find a solution and it is easier to give some shape to the problem as to how best that approach should be implemented and what concrete steps should be taken to ensure that approach to be really translated into practice—the approach which has the unanimous support of Parliament.

Sir, I am aware of the difference of opinion which has been voiced by two hon. Members, Shrimati Lakhanpal and Shri Kishen Chand. The basis of their argument has been that they feel that certain homes have been established, and it is unwise to break up those homes. Shrimati Lakhanpal went a little further and treated these human beings, these unfortunate women, at par either with plants or with dogs, and she said that they should not be treated like that proverbial dog of the washerman, who was neither here nor there. I would very strongly appeal tOthe hon. lady Member not to treat the great womanhood, with regard to which India

[Sarder Swaran Singh.] always has had a great amount of pride and respect, at par either with plants or with dogs. They are imuch more sacred, much higher and much greater than to be just explained away on the analogy of either plants or dogs. They are human beings and they have got to be treated as human beings with greater sympathy and with greater understanding.

I am surprised, Sir, to find that these numbers are not fully appreciated, 30,000 is a colossal figure, and if I may say so, it is several times the membership, say, of the Houses of Parliament. It is as big as a town of the size of the district headquarters. Now, such a large number of people have gone back to their mothers, to their sisters, to their brothers and to their fathers, and to say, with regard to the great bliss flowing from their restitution and restoration to normal circumstances, that there has been uprooting, will be cruel and will not be a proper appreciation of the working of the human mind. We must not forget the atrocious circumstances which were created under barbarous conditions over which those unfortunate creatures had absolutely no control, and to pair off one with the other, I think will not be justified. Therefore, if this problem is viewed in the context that the so-called new ties, which are described as homes, are really nothing but an evolution of some terrible circumstances, their resignation to those deteriorating conditions cannot be any source of satisfaction. No slave can be tolerated to have his chains, even if he likes them. All efforts should be made to break those chains in order that the slave may be able to have an opportunity to decide for himself as to what is going to be his future. The original extent of criticism, when it was strongly felt by the hon. Members of this House that every effort should be made to take a decision about the future of a woman in accordance with her wishes, had very great force, and the agreement arrived at was in consonance with the new approach. Under the agreement it has been provided that she is only to be kept in a home where she can meet her natural relations, and thereafter, if in a calm moment she decides that she has to go back, then she can go back to her natural relations, or she can also elect to stay in the country where-from she was recovered.

Sir, there is a certain amount of dislocation, as has been pointed out by Shri Mathur and also by Shri Kishen Chand. But on the other hand, the amount of satisfaction that flows after this slight dislocation, to my mind, far outweighs that inconvenience which results from the taking away of that woman from that particular home. Is the society entitled to presume that she is really happy, or that she has no desire to go back? I submit that it will be a very dangerous presumption if we start on this basis. If we assume that she is helpless and she has resigned herself, or she has reconciled herself to those wretched conditions, I think, that will not be a safe presumption. We should rather continue to create the conditions in which she. even at the risk of that slight dislocation, is brought to a friendly camp where she has got the opportunity of meeting her relations, and thereafter a decision is taken in accordance with her wishes. In the first instance, even if she has to remain here, it builds her up psychologically. She has had the opportunity of meeting her natural relations. It may be that she has explained to them that "I have built the home here. There is no point in my going across. We can meet each other by going across to the other country on normal passport or after obtaining the necessary visas." Also the natural feeling of weight upon her conscience which will otherwise always remain on her that either she is hated by her natural relations or she has never had the opportunity of thinking for herself, that weight will be removed from her mind and even if thereafter she elects to remain

here—it is on all accounts quite probable and that is also the experience— that even if she goes back to the abductor, she goes back a happier woman as compared to the wretched j condition in which she was recovered. If on the other hand she goes across i and tries to join her natural relations and goes over to the other country, then it was obviously a case in which she was being kept there against her will and when that requisite pressure is removed, she comes back to her own self and wants to go over to her natural relations. Therefore, from whatever angle we view it, the fact that she is put to this inconvenience is very much balanced by the good results flowing from this removal to the camps. These were the conscientious objections. I have kept a note of the various suggestions that have been made by the hon. Members of this House as to how best we should approach this problem. I myself believe that a greater emphasis on the social angle and utilization of social workers in a more effective way will solve this problem much better and will also save the administration and the organisation from a certain amount of criticism. I want however to add, Mr. Deputy Chairman, that Government has been alive to this aspect and from the very inception, a large number of social workers, both women and men, have remained associated with this work at various levels. The persons who have been in charge of these camps have a very difficult and delicate task when persons who can be described as psychological wrecks are recovered and brought to these camps. To take care of them is really a very difficult task and this task has always been handled by social workers. Then again, ample opportunities have been provided for social workers from both the countries to have free access to these unfortunate victims so that they can explain to them the conditions and could bring certain facts to their knowledge which might have the effect of dispelling the fear complex to which those women have been subjected. This is the normal story that is told to these people that their natural relations were all killed or that as soon as they cross the border, they will perhaps be shot down or they will be murdered—this is the type of stories that are normally dinned into the ears of these women before they are recovered. As soon as they go to the camps and meet their own relations, then all that is removed and they see that those relations who were described by the abductors as dead, are alive and they can talk to them. They can also explain to them that such and such women that went over is living happily with either her previous husband or her father or her mother or her other relations. Therefore, that gives an opportunity for all these social workers to explain things in their proper perspective so that these falsehoods that are dinned into their ears are removed and they can think for themselves as to what is the best course that they should adopt. There will, however, always have to be a certain corps of what Mr. Bhupesh Gupta in his characteristic eloquence, was pleased to describe as bureaucratic set-up because even democracy has to function through permanent services and it is a convenient way of describing the permanent services as bureaucratic. The main burden will have to remain on the members of the permanent services both in the matter of recovery and in the general administrative arrangements with regard to finances, accounts and all other things; but I fully appreciate that the social aspect has to be laid greater stress upon and an opportunity to associate as large a number of social workers as could be associated with this type of work with advantage, should be well availed of.

There is one thing which I want particularly to mention. One or two hon. Members have indicated an element of doubt about the future of these women after they are recovered and restored to their natural relations. I have great pleasure in reporting to this hon. House that our society in this respect has shown a very bright and remarkably good side of their

[Sardar Swaran Singh.] approach. We have dealt with thousands of cases, and cases in which the unfortunate victims may not have been really welcome to their families have been extremely rare; and I was' hoping that the hon. lady Member who made particular reference to ' this point would cite even one case in which a woman who had been restored to her relations was not really respected. I think that the greatness of our society lies in rising to the occasion to meet such difficult situations and in this particular respect, in this particular aspect, large numbers of people had doubts about the future of these Hindu and Sikh abducted women who were brought over to India; but it is a very happy augury and as Prof. Wadia pointed out, it has shown a bright lining to the otherwise dark clouds that our society rose to the occasion and really welcomed these women ^ith open arms knowing fully well the circumstances under which they were placed and the indignities to which they were subjected. Therefore, there may be a theoretical objection on this score but this is certainly not borne out by facts and cir-eunastarjnes.

There is one other aspect which has been stressed by more than one Member. That is about the quantum of work that has been done in Pakistan. I am happy to note that every Member who has touched upon this matter has very rightly avoided suggesting that we should have any approach on this matter in any spirit of competition or in a spirit of counting. That is quite consistent with the high tradition that this Parliament has always built while approaching such problems. But it has been quite strongly suggested that steps should be taken to point out to the Pakistan authorities that while we intend to continue our work because we think that it is good to be done, they should also try to do as much and should try to do more in a spirit ot competition for doing a good thing rather than start approaching this problem in a spirit that we should deteriorate because they are deteriorating. There should be that healthy competition for doing that good work in both the countries. The active support and the moral support and. the approach that has been brought to bear on this problem from different sections of the House, these are ample guarantees that this atmosphere will percolate among the people and they will also start feeling the urgency ol the problem.

It is true that there are a large number of women who are unhappy, either on account of age or the initial circumstances in which they were got hold of, in indecent and desperate hurry, and because the original polished sort of life is disappearing and realities are now showing themselves in their naked form. So quite a big percentage of these women are really unhappy and therefore every effort should be made to recover them and keep them in a neutral home so that a decision can be taken in accordance with the agreement; that appears to be the correct approach.

Two hon. Members have made mention of the Prime Minister's speech on the last occasion when he said that he hoped that the work would be completed within the extension that Parliament gave on the last occasion. In a matter of this nature, Sir, it has been the endeavour of the Government to come before Parliament from time to time. Views had been expressed here doubting the wisdom of coming to Parliament over and over again after the year 1949. Some hon. Members have also suggested and asked why sufficient foresight was not shown in 1949, that we ought to have been able to see the duration of time that would be required to straighten out this problem and we should have asked for legislative powers extending over several years. Sir, in a matter of this nature, the objective before the Government has been to finish this work as early as possible. But the results have been of a continuing character and while dealing with a human problem of this nature, you cannot huddle thousands of people

in **one** group. There are limitations, administrative, social and psychological, in the matter of tackling this problem in any big way and within a short time. Public opinion has also varied from time to time. Sometimes the atmosphere is favourable and sometimes there is some opposition to it. But I want to take this opportunity to pay a tribute to the selfless work put in by the band of social workers who against all odds continue to put in their best effort. Sir, in 1949, Parliament in its wisdom put this legislative measure on the Statute Book for two years and later on it was discovered that work has been continuing and on several occasions this measure had to be extended. I think, that this was inevitable, regard being had to the nature of the problem and it was not on account of any lapse, carelessness or want of zeal in the discharge of the executive functions that devolved upon the Government as a result of this legislative measure. I want to assure hon. Members that this matter has been receiving attention at a fairly high level and Government has never treated this problem purely as a routine matter, but has always devoted considerable time at the highest level, to find out as to what would be the best way of dealing with this problem.

Then again, it has been suggested that we have got two Police representatives on this Tribunal and the lady—Shrimati Bhag Mehta—is only an adviser. Why should she not be made a full-fledged member of the Tribunal? But I may point out that the constitution of the Tribunal has to be agreed upon by both the Governments and it is surely some compliment to our social worker, Shrimati Bhag Mehta, that although she belongs to India, she has been accepted as the Joint Adviser, to advise both the Pakistan Member on the Tribunal as also the Indian Member on the Tribunal. She is the Joint adviser to both the Governments. Personally I have no objection if the lady member can be a full-fledged member; but in that case you will have two members, one being our nominee and the other that of Pakistan and whether that will be a real advantage is a matter which requires further consideration; also whether Pakistan is able to nominate a full-fledged lady member to the Tribunal. It is a matter which can be gone into to see what can be done.

SHRI BHUPESH GUPTA: That should be attempted. You should be in touch with the Government of Pakistan to do this, if it is possible.

SARDAR SWARAN SINGH: Therefore, Sir, I submit that the time for which we are now asking this Bill to be extended really will give us ample opportunity to have the report of the Fact Finding Commission and Government will have no hesitation to take any action, administrative or otherwise, to ensure that this work is carried on and concluded as expeditiously as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up the clause by clause consideration of the Bill. There are no amendments.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Title and the Enacting Formula were added to the Bill.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

SHRI H. C. MATHUR: Would you not permit me a few minutes?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No time, Mr. Mathur.

The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE DELHI JOINT WATER AND SEWAGE BOARD (AMENDMENT) BILL, 1955

THE MINISTER FOR HEALTH (RAJKUMARI AMRIT KAUR): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Delhi Joint Water and Sewage Board Act, 1926, for certain purposes, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

In requesting for this Bill to be taken into consideration, I wish to place before the House just a very brief history to show why this has become necessary and also to show the House that this is a very small and simple measure which has, however, been long overdue. As a matter of fact, this Bill was actually introduced in 1951. As will be very clear from the Statement of Objects and Reasons, the Delhi Municipality alone has been given certain concessions which, in the opinion of the Government of India, have really become completely out of date. Also the sewage effluent had been supplied to a number of private individuals for cultivation purposes at certain rates by the Joint Water and Sewage Board and for a number of years these persons have defaulted payment to the Board.

The purpose of one amendment is to enable us to recover the arrears from such defaulters as arrears of land revenue. Now, under the Delhi Joint Water and Sewage Board Act of 1926, the Board supplies filtered water in bulk to various local bodies in Delhi and receives payment from all of them of the actual cost of supply but the Delhi Municipality alone ....

SHRI KISHEN CHAND (Hyderabad): What is the actual cost of supply?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do yoa want to know the cost to everybody?

SHRI KISHEN CHAND: Yes, Sir.

RAJKUMARI AMRIT KAUR: I am only concerned with the Delhi Municipality. The rate varies according to the local body but what I am saying is that when this Board was constituted the Delhi Municipality was the only body that was given this exemption. We have tried to get back to 1926 and And out whether we could get any papers or anything to show us why this exception was made. Nothing is available either with the Government or with the Chief Commissioner of Delhi. The Delhi Municipality alone has been able to produce a resolution that was passed by it on receipt of a letter the number of which has been given by them. When we brought forward this Bill in 1951, the Delhi Municipality said that it should be excused in the light of the agreement that had been reached and that, in any case, we should defer consideration of the question until the corporation was formed. The question of the formation of the corporation was on the tapis; it was presumed that the corporation would come into being in 1952 and I agreed to defer consideration of the question till 1952. In 1952 the Delhi State Government came into being *&nd* that Government were definitely opposed to a corporation. Therefore, the matter was held up but my colleague the Finance Minister—and I entirely agree with him—feels strongly that the amount that is now being paid increasingly to the Delhi Municipality is really not a legitimate charge on the Government of India. Therefore, it is that we have now come up with an amendment to this Act whereby the Delhi Municipality will come in line with all the other local bodies. It will not be a very great liability on that body.

The legislation envisages two provisions; one, it extinguishes the liability of the Central Government under the proviso to sub-section (I) of section 12; and, secondly, that the charges due